- 20th Year
- Issue: 191
- 21.11.2026 (SATURDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक

कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH



युद्ध के दौर में सांस्कृतिक संबंध की वैश्विक शांति की गारंटी, एससीओ सभ्यता संवाद के महत्वप पर बोले पीएम मोदी



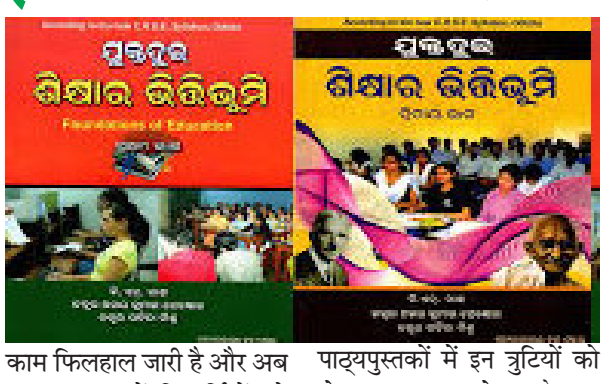
नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वैश्विक शांति को बढ़ावा देने में सज्यतागत संवाद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया भर में चर्चाओं में युद्ध और अशांति छाई हुई है, भारत सांस्कृतिक और सज्यतागत संबंधों पर संवाद कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी के पुराना किला में शंघाई सहयोग संगठन के पहले सज्यतागत संवाद मंच%का उद्घाटन करने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सांस्कृतिक संबंध वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी हैं। उन्होंने कहा यह पहला स्टह सज्यतागत संवाद मंच है। ऐसे समय में जब दुनिया भर में युद्ध और अशांति की चर्चा हो रही है, हम भारत में सज्यतागत संबंधों पर संवाद कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है ज्योंकि सांस्कृतिक संबंध वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी हैं, जो आज के इस कार्यक्रम के महत्व को और भी बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टह की अब तक की यात्रा और उसकी उपलज्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस समूह ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कनेज्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग को काफी मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा कि सज्यतागत और सांस्कृतिक सहयोग सदस्य देशों के बीच संबंधों को और भी मजबूत बनाएगा। उन्होंने कहा कुछ महीने पहले ही शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी स्थापना के 25 साल पूरे किए हैं। इन वर्षों में, SCO ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कनेज्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग को काफी मजबूत किया है। इस संदर्भ में, सांस्कृतिक और सज्यतागत सहयोग हमारे देशों के बीच संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस मंच के उद्घाटन पर भरोसा जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म सांस्कृतिक सहयोग के लिए नए विचार और अवसर पैदा करेगा, जबकि साझा सज्यतागत अनुभव दुनिया को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह मंच नए विचार सामने लाएगा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए नए अवसर पैदा करेगा। साथ ही, हमारे साझा सज्यतागत अनुभव दुनिया को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाएंगे। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। भारत 20 से 22 नवंबर तक इस तीन दिवसीय बहुपक्षीय कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। इसमें स्टह सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और संवाद साझेदारों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र की साझा सज्यतागत विरासत को समझा जा सके और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत किया जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एज्स पर एक पोस्ट में बताया कि पाकिस्तान सहित सभी स्टह सदस्य देशों, साथ ही समूह के पर्यवेक्षकों और संवाद साझेदारों को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत 20-22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में पहले स्टह सज्यता संवाद की मेजबानी कर रहा है। यह स्टह ढांचे के अंतर्गत एक बहुपक्षीय आयोजन है, जिसके लिए पाकिस्तान सहित स्टह के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। स्टह के पर्यवेक्षकों और संवाद भागीदारों को भी इस संवाद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। जयसवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन आज शाम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। यह पहल 2025 में चीन के तियानजिन में आयोजित स्टह शिखर सज्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए उस प्रस्ताव पर आधारित है, जिसमें स्टह ढांचे के तहत सज्यताओं के बीच संवाद के लिए एक समर्पित मंच बनाने का सुझाव दिया गया था। बाद में, स्टह के बिश्केक घोषणापत्र में इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया। उद्घाटन समारोह में सज्यताओं के बीच संवाद सांस्कृतिक कार्यक्रम शीर्षक से एक सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें संगीत, नृत्य, दृश्य कहानी-कथन और वर्णन का समावेश था। वसुधैव कुटुंबकम पूरी दुनिया एक परिवार है की थीम पर आधारित इस प्रस्तुति में भारत और यूरेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों को उजागर किया गया।

यूपी सीएम योगी की मां सावित्री देवी का निधन, ९१ साल की उम्र में ली अंतिम सांस



लखनऊ २०/११ (संवाददाता): उज़र प्रदेश के मुज्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का आज 91 वर्ष की उम्र में उज़राखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर में निधन हो गया। मां के निधन की खबर से मुज्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुज्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और उनकी मां के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने इस कठिन समय में योगी आदित्यनाथ और उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बताया जा रहा है कि सावित्री देवी लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थीं। शुक्रवार सुबह पंचूर गांव स्थित अपने आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मुज्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र ने उनके निधन की पुष्टि की। परिवार और स्थानीय लोगों के मुताबिक, उम्र संबंधी परेशानियों के साथ ही उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। बताया गया कि पिछले काफी समय से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वह मुज्य रूप से अपने परिवार के सदस्यों को ही पहचान पा रही थीं। मां के निधन की सूचना मिलने के समय मुज्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मौजूद थे। वह वहां विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए थे। व्यक्तिगत जीवन के इस बड़े दुख के बावजूद उन्होंने अपने निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा किया। हम आपको बता दें कि पंचूर उज़राखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर क्षेत्र में स्थित है। यही वह गांव है, जहां योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय सिंह बिष्ट के रूप में हुआ था और जहां उनका बचपन बीता।योगी आदित्यनाथ का अपने पैतृक गांव और परिवार से जुड़ाव रहा है। मुज्यमंत्री बनने के बाद भी वह कई मौकों पर पंचूर पहुंचे हैं। फरवरी 2026 में भी उन्होंने अपने गांव का दौरा किया था और परिजनों के साथ समय बिताया था। इससे पहले मई 2022 में भी वह अपनी मां से मिलने पंचूर पहुंचे थे। सावित्री देवी अपने पति आनंद सिंह बिष्ट के निधन के बाद भी गांव में ही रह रही थीं। आनंद सिंह बिष्ट का अप्रैल 2020 में निधन हुआ था। उस समय कोरोना महामारी के कारण लागू प्रतिबंधों और मुज्यमंत्री के प्रशासनिक दायित्वों के चलते योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे।

राज्य में स्कूली किताबों में मिलीं एक हजार से अधिक गलतियां, बांटी गई ७७.८७ लाख संशोधित प्रतियां



भुवनेश्वर २०/११ (संवाददाता): ओडिशा सरकार ने कक्षा पहली से आठवीं तक की पाठ्यपुस्तकों में एक हजार से अधिक त्रुटियां पाये जाने के बाद स्कूली विद्यार्थियों को 77.87 लाख से अधिक संशोधित पाठ्यपुस्तकें वितरित की हैं। राज्य के स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में यह जानकारी दी। कांग्रेस विधायक सागर चरण दास के एक सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा, ''पाठ्यपुस्तकों में पाई गई त्रुटियों के आधार पर एक शुद्धिपत्र तैयार किया गया और सभी स्कूलों को भेजा गया। इसके साथ ही शिक्षकों को निर्देश दिए गए कि कक्षाओं में पढ़ाई के दौरान त्रुटिरहित सामग्री सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाए।'' उन्होंने कहा कि संशोधित पाठ्यपुस्तकों की दोबारा छपाई और वितरण का काम फिलहाल जारी है और अब तक राज्यभर में विद्यार्थियों को 77,87,457 संशोधित पुस्तकें वितरित की जा चुकी हैं। गोंड ने बताया कि राज्य के 50,827 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कुल 39.19 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में व्याकरण, टाइपिंग और वर्तनी संबंधी कुल 1,075 त्रुटियों के अलावा तथ्यों और अवधारणाओं से जुड़ी पांच गलतियां पाई गईं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री में सुधार के लिए 661 सुझाव दिये गये। पाठ्यपुस्तकों में इन त्रुटियों को लेकर व्यापक आलोचना के बाद ओडिशा सरकार ने इन त्रुटियों को स्वीकार किया। अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने तत्कालीन निदेशक और तीन सहायक निदेशकों को निलंबित कर दिया तथा छह अन्य सहायक निदेशकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की।मामले की जांच कर रही अपराध शाखा ने इससे पहले अध्यापक शिक्षा एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (टीई एवं एससीईआरटी) के पूर्व निदेशक मनोज कुमार पाधी (57) को गिरज़्तार किया था।

रामायण फिल्म के आपत्तिजनक दृश्य हटाने की मांग, हिंदू जनजागृति समिति का प्रदर्शन

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): हिंदू जनजागृति समिति ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रामायण' के कुछ दृश्यों को हटाने की मांग को लेकर शुक्रवार को मुंबई और कोल्हापुर में विरोध प्रदर्शन किया। संगठन ने आरोप लगाया कि फिल्म में महर्षि वाल्मीकि की रामायण को गलत तरीके से पेश किया गया है और राक्षस राजा रावण का महिमामंडन किया गया है।

संगठन ने मध्य मुंबई में दादर रेलवे स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। इसी तरह का विरोध प्रदर्शन कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के नाम ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें फिल्म के आपज़िजनक दृश्यों व संवादों को तत्काल हटाने, फिल्म की दोबारा समीक्षा करने और इसके आगामी भागों को रिलीज से पहले संतों, रामायण के विद्वानों तथा हिंदू धर्मग्रंथों के विशेषज्ञों को दिखाना अनिवार्य करने की मांग की गई। हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता उदय धुरी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ी 'रामायण' में बदलाव कर रचनात्मक स्वतंत्रता की आड़ में किसी खास विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश हिंदू समुदाय बर्दाश्त नहीं करेगा।

उन्होंने कहा इसमें निहत्था रावण हजारों लोगों से लड़ता दिखाया गया है, जबकि हथियारों से लैस भगवान श्रीराम और लक्ष्मण राक्षसों को देखकर भागते नजर आते हैं? भारत रामायण की ऐसी विकृत प्रस्तुति बर्दाश्त नहीं करेगा।

खुद लौटना चाहती हैं शेख हसीना, पर नया पासपोर्ट न देकर वापसी टाल रहा ढाका



नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर बांग्लादेश का जोर, असल में उनकी स्वदेश वापसी में देरी कराने की एक चाल है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना अगर अपनी मर्जी से वापस लौटना चाहें, तो भारत की ओर से इसमें कोई रुकावट नहीं है। यह बात तब सामने आई जब अवामी लीग की इस नेता ने नए पासपोर्ट के लिए दूसरी बार अनुरोध किया। 79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह में अपनी सरकार के सज़ा से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं। हाल के साक्षात्कारों में जिसमें ।ज्ञ के साथ हुआ साक्षात्कार भी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो। 9 नवंबर को, हसीना की ओर से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म %मैट्रिज़्स चैज़्बर्स% ने नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा। इस पर ढाका के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि इस अनुरोध के लिए हसीना की ओर से कोई आधिकारिक अनुमति (ऑथराइजेशन) नहीं दी गई थी। इसके बाद, गुरुवार को मैट्रिज़्स चैज़्बर्स ने उच्चायोग को एक दूसरा पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला एक अनुमति पत्र भी शामिल था, जो उन्हें उनकी ओर से कार्रवाई करने का अधिकार देता है। 9 नवंबर को हसीना के इस अनुरोध के तुरंत बाद, बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण (वापसी) पर जोर देगी।

आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल पर 60 दिनों का प्रतिबंध

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): दिल्ली पुलिस ने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के पालम उपमंडल के अंतर्गत आने वाले इलाकों में शादी, पार्टियों और अन्य समारोहों के दौरान लेजर बीम के इस्तेमाल पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस ने यह कदम विमान के उतरने के दौरान लेजर बीम से पायलटों का ध्यान भटकने के खतरे को देखते हुए उठाया है। सहायक पुलिस आयुक्त प्रदीप कुमार मीणा की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत जारी यह आदेश 18 नवंबर से लागू हो गया है और 16 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार, आईजीआई हवाई अड्डे के हवाई यातायात नियंत्रण (एटीसी) ने कई ऐसी घटनाओं की जानकारी दी थी, जिनमें लेजर बीम के कारण विमान उतारते समय पायलटों को देखने में परेशानी और ध्यान भटकने का सामना करना पड़ा। आदेश में कहा गया है कि इस तरह की घटनाएं न केवल परेशानी पैदा करती हैं, बल्कि यात्रियों, चालक दल के सदस्यों और विमानों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा भी बन सकती हैं। पुलिस ने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास और उसके नजदीकी इलाकों में कई फार्महाउस, बैंक्वेट हॉल, होटल और रेस्तरां खुल गए हैं, जहां शादी समारोहों, पार्टियों और अन्य आयोजनों के दौरान लेजर बीम सहित तेज रोशनी का अज्सर इस्तेमाल किया जाता है। आदेश में कहा गया है, ''रात के समय खुले स्थानों पर इस तरह की लेजर बीम का इस्तेमाल चिंता का विषय बन गया है, ज्योंकि इससे विमान उड़ाने वाले पायलटों की दृष्टि सीधे प्रभावित हो सकती है। मानव जीवन को खतरे से बचाने और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आईजीआई हवाई अड्डे के आसपास लेजर बीम के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के तत्काल उपाय करना जरूरी है।'' यह प्रतिबंध पालम उपमंडल के तहत आने वाले क्षेत्र में सभी व्यक्तियों, समूहों, कार्यक्रम आयोजकों, बैंक्वेट हॉल, होटल, रेस्तरां, इमारतों और अन्य संपज़ियों पर लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

ओडिशा तट पर कर गया अकवान, नहीं हुआ बड़ा नुकसान पर भारी बारिश जारी



भुवनेश्वर २०/११ (संवाददाता): ओडिशा में शुक्रवार सुबह गोपालपुर के पास तट से टकराए चक्रवात 'अकवान' के कारण अब तक बड़े नुकसान या किसी की मौत की खबर नहीं है लेकिन इसके प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई है। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने एक बुलेटिन में बताया कि चक्रवात के दस्तक देने की प्रक्रिया सुबह करीब आठ बजे शुरू हुई और पूर्वाह्न 11 बजकर 20 मिनट पर पूरी हुई। आईएमडी ने सुबह 11 बजकर 20 मिनट पर जारी बुलेटिन में कहा, चक्रवाती तूफान अकवान ने सुबह सात बजकर 30 मिनट से आठ बजकर 30 मिनट के बीच 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रज़्तार वाली हवाओं और 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक के झोंकों के साथ गोपालपुर के पास दक्षिणी तटीय ओडिशा और उज़री आंध्र प्रदेश को पार किया। इसके तट पर पहुंचने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मौसम विभाग ने दोपहर एक बजे जारी बुलेटिन में बताया कि चक्रवाती तूफान कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। दक्षिणी तटीय ओडिशा में इसके साथ 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रज़्तार से हवाएं चल रही हैं, जिनकी गति झोंकों के साथ 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही है। बुलेटिन में कहा गया कि गहरे दबाव का यह क्षेत्र उज़र-उज़रपूर्व दिशा की ओर बढ़ने और अगले छह घंटों में धीरे-धीरे कमजोर होकर दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। इसके बाद अगले छह घंटों में इसके और कमजोर होकर स्पष्ट रूप से चिह्नित कम दबाव के क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। चक्रवात के प्रभाव से ओडिशा में भारी बारिश हुई।

गंजाम जिले के पात्रापुर में सर्वाधिक 209 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके बाद इसी जिले के हिंजिली में 207 मिलीमीटर, चिकिटी में 199 मिलीमीटर, गोपालपुर में 190 मिलीमीटर और छत्रपुर में 139 मिलीमीटर बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा, दक्षिणी ओडिशा में अब भारी बारिश हो रही है और उज़री हिस्से में भी बाद में भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि शनिवार से बारिश की तीव्रता कम हो जाएगी। भुवनेश्वर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा कि गंजाम के बाद पुरी में भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद जगतसिंहपुर में भी भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर समेत खुर्दा जिले में भी भारी बारिश होगी। आईएमडी ने 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट (तैयार रहने की चेतावनी) जारी किया है। इन जिलों में शनिवार सुबह आठ बजकर 30 मिनट तक 12 से 20 सेंटीमीटर तक बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं, 11 जिलों के लिए येलो चेतावनी (अपडेट रहने की सलाह) जारी की गई है, जहां सात से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को शनिवार तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह भी दी है। मुज्य सचिव अनु गर्ग ने कहा, स्थिति नियंत्रण में है। विभिन्न जिलों में बारिश दर्ज की गई है।



विविध समाचार



कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बोले राहुल गांधी- २०१४ चुनाव में गड़बड़ी के सबूत थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने कहा था-३०० प्रतिशत पक्के सबूत बिना मत बोलिए

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनावों में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बावजूद पार्टी द्वारा चुनाव बहिष्कार करने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से दूर रहने का अर्थ भारतीय लोकतंत्र को त्याग देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने 2014 और 2024 के लोकसभा चुनावों तथा भारत निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कई बड़े दावे किए।

उन्होंने तर्क दिया कि चुनावों से दूर रहने का मतलब भारतीय लोकतंत्र को छोड़ देना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान, गांधी ने दावा किया कि उनके पास 2014 के लोकसभा चुनावों में हुई गड़बड़ियों के सबूत थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस बारे में न बोलने की सलाह दी थी। पार्टी का जोर इस बात पर था कि चुनावी प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने से पहले 100, 200, 300 प्रतिशत सबूत होने चाहिए। बुधवार को अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, 卐अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। विपक्ष की रणनीति के बारे में बताते हुए गांधी ने कहा कि वे चुनाव लड़ना जारी रखेंगे और साथ ही उन गड़बड़ियों को भी उजागर करेंगे जो उनके अनुसार हो रही हैं, भले ही इसके लिए उन्हें राजनीतिक नुकसान ही ज़्यों न उठाना पड़े। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी रणनीति यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उसे सामने लाएं और तब तक नुकसान सहते रहें, जब तक कि भारत के लोगों को यह एहसास न हो जाए कि पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन हम चुनावी ढांचे को तोड़ना नहीं चाहते हैं। गांधी की यह टिप्पणी कांग्रेस के लगातार चल रहे %वोट चोरी% अभियान के बीच आई है। इस अभियान के जरिए पार्टी ने मतदाता सूची और चुनाव कराने की प्रक्रिया में गड़बड़ियों का आरोप लगाया है। विपक्ष ने बार-बार भारत निर्वाचन आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, साथ ही यह भी कहा है कि वे चुनावी प्रक्रिया में



हिस्सा लेना जारी रखेंगे।

कार्यक्रम में बोलते हुए, गांधी ने यह भी दावा किया कि उनके पास 2014 के लोकसभा चुनावों में हुई गड़बड़ियों के सबूत थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इस बारे में बात न करने की सलाह दी थी।

उन्होंने बताया कि 2014 के चुनावों में जीत का अंतर असामान्य रूप से बहुत बड़ा और अस्पष्ट था, जिससे पार्टी के भीतर संदेह पैदा हुआ था। हालांकि, शुरुआत में कांग्रेस के पास अपनी चिंताओं को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। 2014 के चुनावों के दौरान ही हमें लग गया था कि कुछ गड़बड़ है, ज़्योंकि जीत-हार के अंतर (मार्जिन) को समझाना मुमकिन नहीं था। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। जब मुझे आखिरकार सबूत मिल गया और मैंने कांग्रेस के अपने राजनीतिक नेताओं को दिखाया, तो उन्होंने मुझसे कहा, कृपया ऐसा मत कहिए, उन्होंने बताया। गांधी ने आगे बताया कि वे चुनावी प्रक्रिया पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाने से ज़्यों हिचकिचा रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र को पवित्र मानती है, और इस तरह की चिंताएं जताने के लिए बहुत पक्के सबूतों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक कि मेरे पास 100, 200 या 300 प्रतिशत पक्के सबूत न हों।

कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष को चुनाव आयोग के भीतर से ही जानकारी मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी ही अब वहां के कामकाज से असहज महसूस कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, चुनाव आयोग खुद हमें जानकारी दे रहा है। अंदर से। उन्होंने दावा किया कि वरिष्ठ अधिकारी मौजूदा हालात में काम करते रहने में अपनी असमर्थता जता रहे हैं। गांधी ने कहा, यह बस समय की बात है कि यह ढांचा कब ढह जाए। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अब कह रहे हैं कि देखिए, अब हम और काम नहीं कर सकते।

2024 के लोकसभा चुनावों का जिक्र करते हुए, कांग्रेस नेता ने मतदाताओं के साथ छेड़छाड़ (वोटर मैनिपुलेशन) के आरोप फिर से दोहराए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मतदाता सूची में फर्जी या अयोग्य लोगों के नाम शामिल हैं, तो चुनावों की विश्वसनीयता ज़्या रह जाएगी? ब्राजील की एक महिला का उदाहरण देते हुए गांधी ने दावा किया कि वह कभी भारत नहीं आई, फिर भी उसने भारत में एक राज्य चुनाव के दौरान 23 बार वोट डाला। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी चुनावी धांधली के खिलाफ अपना अभियान जारी रखेगी।

उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष ऐसे भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा हो। उन्होंने कहा, हम एक गैर-लोकतांत्रिक भारत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि भारत के ज्यादातर लोग भी सोचते हैं।

कोलकाता के गिरीश पार्क थाने पहुंचे अभिषेक बनर्जी, बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाए चोर-चोर के नारे

कोलकाता २०/११ (संवाददाता): जब तृणमूल कांग्रेस (ञरूष्ट) के सांसद अभिषेक बनर्जी कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चोर-चोर के नारे लगाए। बनर्जी के आने की खबर मिलते ही ञरूष्ट समर्थक भी पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए। उनके नारे लगाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी चोर-चोर के नारे लगाए, जिससे दोनों गुटों के बीच नारेबाजी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता और वकील नाज़िया खान ने बताया कि 31 अज़्टूबर 2026 को गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, और पुलिस ने उन्हें 20 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। खान ने कहा 31 अज़्टूबर 2026 को कोलकाता के गिरीश पार्क पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले के सिलसिले में, पुलिस ने अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए 20 नवंबर को पुलिस



स्टेशन बुलाया है। खान ने बताया कि इस मामले में बनर्जी को अपना बयान दर्ज कराना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वह पुलिस स्टेशन नहीं आते हैं, तो वे कलकज़ा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके उनके खिलाफ सज़्त कार्रवाई की मांग करेंगे। उन्होंने कहा अभिषेक बनर्जी को इस मामले में अपना बयान दर्ज कराना है। अगर वह आज पुलिस स्टेशन नहीं आते हैं, तो हम कलकज़ा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ सज़्त कार्रवाई की मांग करेंगे। खान ने कहा अभिषेक बनर्जी ने जो किया है, उसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच, टीएमसी नेता उपासना चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें पहले ही आशंका थी कि बीजेपी के कुछ गुंडे यहां आकर हंगामा करने की कोशिश करेंगे। और अभी हम ठीक यही देख रहे हैं। आप सब देख सकते हैं कि वे कैसे चिल्ला रहे हैं और %चोर-चोर% के नारे लगा रहे हैं। चौधरी ने दावा किया कि मौके पर मौजूद टीएमसी कार्यकर्ता शांत हैं और वे बीजेपी के नारों का जवाब नारों से नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा हम कोई नारेबाजी नहीं करना चाहते। हम बस एक बात कहेंगे- 4 तारीख के बाद से अभिषेक दा को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और अभी भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी डरते नहीं हैं, और हम भी नहीं डरते—यानी अभिषेक बनर्जी की टीम और पार्टी के सदस्य। हम इस तरह से नहीं डरते, इसलिए उन्हें हमें डराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।卐 दूसरी ओर, बीजेपी समर्थक सुशील पांडे ने टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में 15 सालों से चोरी और सिंडिकेट का काम चल रहा है।

पांडे ने कहा आप चोरी को रोकने की बात नहीं कर रहे हैं; बल्कि आपने खुद चोरी की है। आप 15 सालों से चोरी कर रहे हैं। कोयले की चोरी करना, बाली में चोरी के सिंडिकेट चलाना। अब यह सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पुराने तौर-तरीके अब नहीं चलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि नई सरकार जनहित में काम करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कोयले और अन्य गतिविधियों से जुड़े सिंडिकेट और घोटालों को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जो सरकार आई है, वह निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से काम करेगी। इसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा; जो कुछ भी होगा.

जमानत पर रिहा होकर रामपुर पहुंचे आजम खान ने भरी हुंकार, कहा-आगामी यूपी चुनाव महज चुनाव नहीं, बल्कि इंकलाब होगा

रामपुर २०/११ (संवाददाता): धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में गिरज़्तारी के बाद जमानत पर रिहा हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने बुधवार देर रात अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचकर राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी। गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होने के बाद रामपुर पहुंचने पर बड़ी संज़्या में मौजूद समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आजम खान ने आगामी उज़र प्रदेश विधानसभा चुनाव, संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर तीखे बयान दिए। आगामी उज़र प्रदेश विधानसभा चुनावों के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए आजम खान ने दावा किया कि इस बार प्रदेश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। उन्होंने कहा, इस बार चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा। बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा। सपा नेता



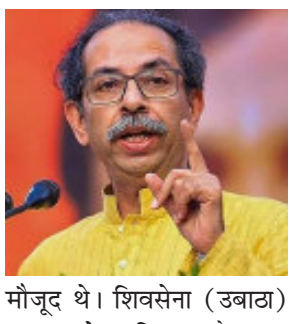
के अनुसार, अब प्रदेश की जनता धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर वास्तविक मुद्दों पर लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उन जैसे लोग संविधान और विधान की रक्षा के लिए मरने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और भविष्य में भी तैयार रहेंगे।

उन्होंने कहा, ''अब लोग धर्म और जाति के नाम पर नहीं लड़ेंगे। मुद्दों पर लड़ाई होगी और हम जैसे लोग संविधान के लिए और विधान के लिए मरने के लिए तैयार थे, तैयार हैं और तैयार रहेंगे।'' सपा प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान पर कि प्रदेश में पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान को न्याय दिलाया जाएगा, उन्होंने कहा, ''न्याय तो न्याय है, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया जाएगा।'' मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी जैसे आरोपों का भी सामना कर रहे खान ने तंज भरे अंदाज में कहा कि अगर मुर्गी, बकरी और भैंस चोरी करने वाला व्यक्ति प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोपी हो सकता है और वह विश्वविद्यालय बनाता है तो उनकी अल्लाह से दुआ है कि हर गली में एक मुर्गी चोर पैदा हो ताकि वह विश्वविद्यालय बना सके। उन्होंने कहा, ''जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन्हें यह सोचना चाहिए कि उनकी साख कितनी गिर गई है और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय उनके बारे में ज़्या राय रख रहे हैं...उन्हें थोड़ा-सा अपना स्तर बचा कर रखना चाहिए।''

खान ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि अगर मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान के जमाने में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण होते तो यह दोनों भी जेल में होते। आजम खान को धनशोधन मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा कर दिया गया। खान को ईडी ने उनके मोहज़्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धनशोधन मामले में 31 अज़्टूबर को हिरासत में लिया था। उसी दिन उन्हें रामपुर जेल से एक अन्य आपराधिक मामले में रिहा किया गया था। गिरज़्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

भाजपा से २०१९ के बाद बातचीत हमेशा के लिए बंद हो गई-ठाकरे

मुंबई २०/११ (संवाददाता): शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी की पूर्व सहयोगी भाजपा के साथ बातचीत 2019 में बंद हो गई थी और फिर कभी शुरू नहीं हुई। शिवसेना (उबाठा) सांसद और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत की नयी पुस्तक बोध कीर्तन के विमोचन कार्यक्रम में, ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुज़्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दो दिन पहले की गई टिप्पणी का जिक्र किया। एक अन्य पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में फडणवीस ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था कि जब भी उद्धव ने उन्हें फोन किया, उन्होंने हमेशा सकारात्मक जवाब दिया। मुज़्यमंत्री ने कहा, ''वर्ष 2019 के बाद उन्होंने फोन नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा था।'' उस विमोचन कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे दोनों



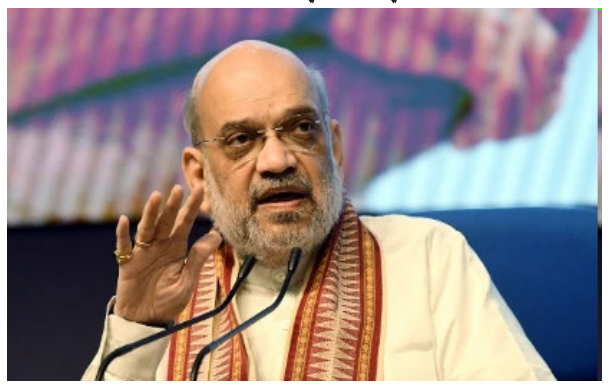
मौजूद थे। शिवसेना (उबाठा) प्रमुख ने शनिवार के एक कार्यक्रम में कहा, ''कुछ लोगों को फोन आने बंद हो गए... और फिर वे (हमेशा के लिए) बंद हो गए।'' महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, अविभाजित शिवसेना मुज़्यमंत्री के पद को लेकर अपने पुराने सहयोगी भाजपा से अलग हो गई। वर्ष 2022 में शिवसेना में टूट होने और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के भाजपा से हाथ मिलाने के बाद, दोनों के बीच रिश्ते और भी ज़्यादा खराब हो गए। बोध कीर्तन पुस्तक में राउत के दार्शनिक चिंतन और अनुभव शामिल हैं।

कश्मीर 35 साल बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया-अमित शाह

नयी दिल्ली २०/११ (संवाददाता): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलज़्धि के तहत कश्मीर 35 साल बाद स्थानीय रूप से भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने देश की आतंकवाद रोधी नीति में सक्रिय कार्रवाई को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वार्षिक आतंकवाद रोधी सज़्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने यहां कहा कि पूरे आतंकवादी नेटवर्क की जांच की जानी चाहिए और उसकी क्षमताओं को समन्वित तरीके से ध्वस्त किया जाना चाहिए।

शाह ने कहा कि आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों से जुड़ी समस्या को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विदेश में छिपे अपराधियों को वापस लाना जरूरी है। शाह ने कहा, जब तक हम समन्वित और व्यापक तरीके से पूरे आतंकवादी नेटवर्क पर प्रहार नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। शाह ने आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति को जमीन पर निर्णायक परिणाम मिलने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, लश्कर आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब भारत में जन्मे और स्थानीय स्तर पर भर्ती हुए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। यह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम उपलज़्धि है। उन्होंने कहा कि 35 साल बाद ऐसी स्थिति बनी है। भट बुधवार को जज़्मू-कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था।

वह कुलगाम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की चौकी पर 11 नवंबर को हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में वांछित था और उस पर 15 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान घायल हो गए थे। शाह ने कहा,आतंकवाद, संगठित अपराध और मादक

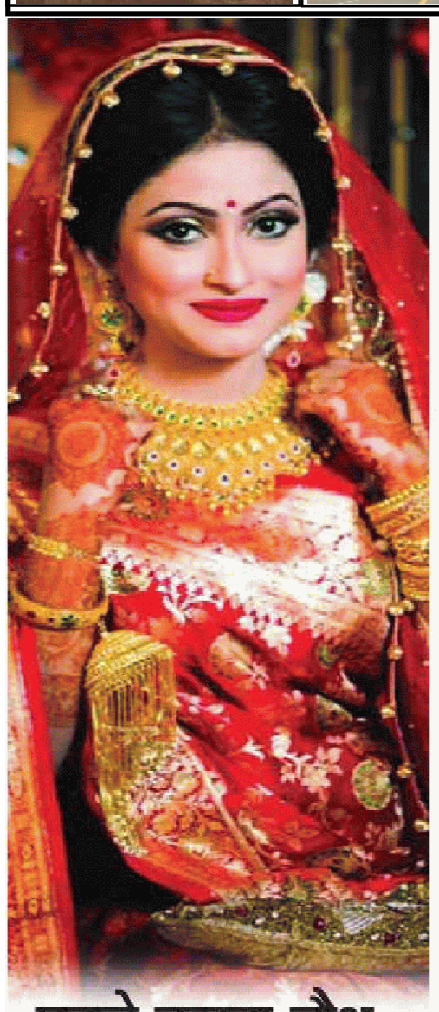


पदार्थों के तीनों खतरों को पूरी तरह खत्म करने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों और साजिशकर्ताओं को भारतीय अदालतों के समक्ष लाना जरूरी है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का उल्लेख करते हुए कहा कि 2019 से अब तक केंद्रीय अन्वेषण ज़्यूरो (सीबीआई), गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों के समन्वित प्रयासों तथा वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल से 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है और हम लंबे समय से इसका सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलग-अलग राज्यों की पुलिस ने कई प्रयास किए, लेकिन उनमें आपसी तालमेल की कमी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। शाह ने कहा, समय बीतने के साथ अलग-अलग सरकारों के कार्यकाल में इन कमियों को दूर करने के लिए धीरे-धीरे प्रयास किए गए। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि इतने विशाल देश में - कश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारका से कामाज़्या तक - हम एक ऐसी व्यवस्था लागू कर रहे हैं, जिसके तहत आतंकवाद से निपटने के लिए एक समान रणनीति हर पुलिस थाने के स्तर तक काम करेगी।卐 उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित संगठन 'पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (पीएफआई) के नेटवर्क का खात्मा इस बात का बड़ा उदाहरण है कि पूरे भारत में पुलिस बलों की ओर से चलाए गए समन्वित अभियान कितने प्रभावी हो सकते हैं। शाह ने कहा कि एक ही रात में, 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर पीएफआई के नेटवर्क को बड़ा झटका दिया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है। शाह ने कहा कि पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद भट्टी द्वारा संचालित शहजाद भट्टी नेटवर्क को गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि देशभर में इसके 40 से अधिक गिरोह ध्वस्त किए गए हैं, 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 271 से ज़्यादा लोगों को गिरज़्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी सफल एजेंसी की पहचान यह है कि वह आतंकवादियों को किसी आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही गिरज़्तार कर जेल भेज दे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को इस मॉडल का विश्लेषण कर इसे स्वीकार करना चाहिए और अपने-अपने क्षेत्रों में लागू करना चाहिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय सज़्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ साझा कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पूरे नेटवर्क की जांच करने से कई घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकता है। शाह ने कहा कि कानूनी मोर्चे पर गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत किया गया है और संस्थागत स्तर पर सूचनाओं के आदान-प्रदान को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने की जरूरत है।




विविध समाचार



पहले करवा चौथ पर क्या है शादी का जोड़ा पहनने का महत्व?

लोक मान्यता है कि पहले करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को शादी का जोड़ा पहनना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शादी का जोड़ा विवाह के समय बहुत पवित्र हो जाता है।

करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लम्बी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और करवा माता एवं चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहनती हैं। विशेष रूप अगर पहला करवा चौथ है तो शादी के जोड़े को दोबारा इस दिन पहनने का विधान है। ऐसे में ज्योतिषाचार्य राधाकांत वत्स से आइये जानते हैं कि आखिर क्यों पहले करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पहनती हैं शादी का जोड़ा और क्या हैं उससे मिलने वाले लाभ।

पहले करवा चौथ पर क्यों पहना जाता है शादी का जोड़ा?

लोक मान्यता है कि पहले करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को शादी का जोड़ा पहनना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शादी का जोड़ा विवाह के समय बहुत पवित्र हो जाता है। फेरों के दौरान जब शादी के जोड़े को पहने लड़की अग्नि के चक्कर लगाती है तब उस अग्नि के प्रभाव से वह जोड़ा शुद्ध हो जाता है। वहीं, जब इस पवित्र जोड़े को शादी के बाद पहले करवा चौथ पर दोबारा पहना जाता है, तब इसकी शुद्धता से पूजा में पवित्रता और बढ़ जाती है। साथ हीं, वैवाहिक जीवन में इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता आने लगती है। दांपत्य जीवन का क्लेश दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। इसके अलावा, करवा चौथ के दिन शादी का जोड़ा पहनने से पति-पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। हालांकि शादी का जोड़ा पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह गंदा न हो या कहीं से भी फटा-कटा न हो नहीं तो इससे पूजा में दोष लगता है और वैवाहिक जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। क्लेश बढ़ने लगता है।



करवा चौथ पर इंडो वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहनें ये ज्वेलरी

सुंदर दिखना हम सभी को पसंद होता है। लेकिन लुक तभी अच्छा लगता है, जब आप अलग-अलग तरह के लुक को रीक्रिएट करते हैं। इस बार आप इंडो वेस्टर्न आउटफिट को स्टाइल करें। इससे आपके लुक में कुछ डिफरेंट डिजाइन ऐड होगा। इसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए साथ मे ज्वेलरी वियर करें। मार्केट में कई सारी फैंसी डिजाइन वाली ज्वेलरी मिलती है। इसे स्टाइल करके आप अपने लुक को परफेक्ट बना सकती हैं।

हैवी चोकर नेकलेस सेट

अगर आप ऑफ शोल्डर ड्रेस को स्टाइल कर रही हैं, तो इसके साथ आप हैवी चोकर सेट को स्टाइल कर सकती हैं। इस तरह के चोकर सेट में आपको मल्टी लेयर और कलर दोनों मिल जाएंगे। इसलिए इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहना जा सकता है। मार्केट में इस तरह के सेट आपको आसानी से मिल जाएंगे। जिसे आप 200 से 300 रुपये में खरीद सकती हैं। बस आपको अपनी गर्दन का ध्यान रखना है और एक बार ट्राई जरूर करना है। इससे आप सेट के डिजाइन को सही तरीके से देख पाएंगी।

इयरकफ करें स्टाइल

बड़े-बड़े इयररिंग्स या झुमकी की जगह पर आप इयरकफ को स्टाइल करें। इस तरह के इयरकफ पहनने के बाद अच्छे लगते हैं। इसमें आपको काफी सारे अलग-अलग डिजाइन मिल जाएंगे। जिसे आप अपनी ड्रेस से मैच करके वियर करें। आप चाहें तो सिंपल डिजाइन वाले खरीदकर भी वियर कर सकती हैं, ताकि इसे दोबारा किसी और ड्रेस के सात मैच किया जा सके। आपके इस तरह के इयररिंग्स पहनने के बाद अच्छे लगेंगे। साथ ही, ये आपको मार्केट में 100 से 200 रुपये में मिल जाएंगे।

बैंगल्स को करें वियर

आउटफिट के साथ सेट और इयररिंग्स हर कोई पहनता है, लेकिन आप हाथों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बैंगल्स को भी स्टाइल करें। आजकल कांच के साथ-साथ मेटल और ऑक्सीडाइज्ड डिजाइन में बैंगल्स मिल जाएगी, जो वियर करके अच्छी लगेगी। इसमें आप चाहें तो पूरा सिंगल सेट भी ले सकती हैं। मार्केट में ये आपको 200 से 300 रुपये में मिल जाएगा। जब आप इसे आउटफिट के साथ वियर करेगी, तो हाथ सुंदर लगेंगे।

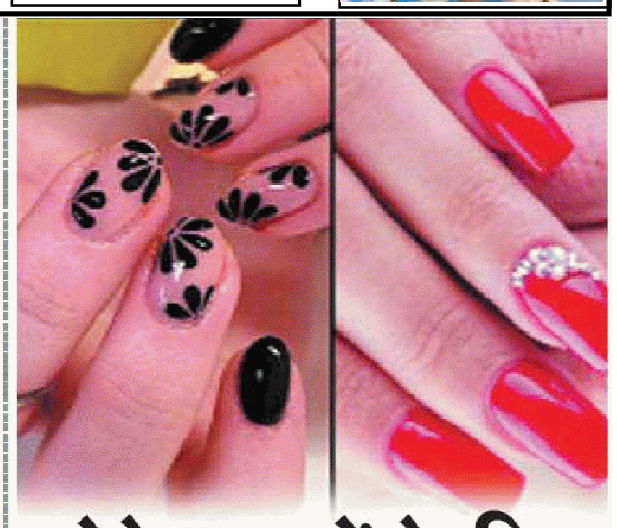


करवाचौथ के दिन घर पर ही करें पेडीक्योर जानें सही तरीका

हम सभी चाहते हैं कि हमारे पैर खूबसूरत नजर आए और इसके लिए हम आए दिन पार्लर में जाकर पेडीक्योर भी करवाते हैं। बदलते मौसम में त्वचा भी भी बदलने लगती है। ऐसे में बार-बार पार्लर में जाकर पैसे खर्च करना हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। वहीं क्या आप जानती हैं कि आप बिना पैसे खर्च किए भी पेडीक्योर कर सकती हैं। तो आइये आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे ब्लीच एक्टिवेटर की मदद से आप पैरों को साफ कर सकती हैं। साथ ही, बताएंगे पेडीक्योर करने का आसान तरीका-

कैसे करें घर पर पेडीक्योर?

- सबसे पहले अपने पैरों को पानी से धो लें और तौलिए की मदद से सुखा लें। इसके बाद एक टब में गुनगुने पानी में लगभग 5 मिनट तक पैरों को भिगोकर रखें।
- इसके बाद आप एक बाउल में ब्लीच के साथ में मिला और एक्स्ट्रा बचा हुआ एक्टिवेटर डालें और जरूरत अनुसार पानी मिलकर पेस्ट तैयार कर लें।
- ध्यान रहे कि सेंसिटिव स्किन पर ब्लीच एक्टिवेटर या किसी भी अन्य चीज का इस्तेमाल करने से बचें और एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना कुछ भी त्वचा पर न लगायें।
- इसके बाद पेस्ट को पैरों में अच्छी तरह से लगा लें। पमिस स्टोन की मदद से पैरों पर हल्के हाथों से मसाज करें ताकि टैनिंग और पैरों में मौजूद गंदगी अच्छी तरह से निकल जाए।
- लगभग 10 से 15 मिनट इस पेस्ट को पैरों में लगा रहने दें। टब में मौजूद गुनगुने पानी की मदद से पैरों को साफ कर लें।
- तौलिए की मदद से पैरों को साफ करें और बॉडी मॉइस्चराइजर की मदद से त्वचा को ड्राई होने से बचाएं।
- इस तरह आप हफ्ते में 1 से 2 बार तक ब्लीच के साथ मिले एक्स्ट्रा एक्टिवेटर की मदद लेकर पैरों को साफ कर सकती हैं।
- बता दें कि यह स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंटका काम भी करता है।



छोटे नाखूनों के लिए परफेक्ट हैं नेल आर्ट के ये डिजाइंस

नाखूनों को खूबसूरत बनाने के लिए उनकी सही तरीके से देखभाल करना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए आप घर पर ही मैनीक्योर और पेडीक्योर कर सकती हैं।

हम सभी चाहते हैं कि हमारे नाखून खूबसूरत नजर आए और इसके लिए हम आए दिन बाजार से नए-नए नेल आर्ट करवाना पसंद करते हैं। नेल आर्ट के कई डिजाइंस आपको ऑनलाइन देखने को भी मिल जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे डिजाइन आपके नाखूनों पर खूबसूरत नजर आए। वहीं नेल शेप के अनुसार भी डिजाइन को चुनना बेहद जरूरी होता है। खासकर छोटे नाखूनों के लिए नेल आर्ट के डिजाइन को चुनने में दिक्कत होती है। तो आइये आज हम आपको दिखाने वाले हैं छोटे आकार के नाखूनों के लिए नेल आर्ट के ये लेटेस्ट डिजाइंस। साथ ही, बताएंगे इन नेल आर्ट के डिजाइन को बनाने का आसान तरीका-

स्टोन नेल आर्ट डिजाइन

स्टोन में आपको कई तरह के डिजाइन और कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। मिनिमल और सिंपल लुक के लिए आप किसी भी कलर का नेल पेंट लगाकर इस पर ग्लिटर ग्लू की मदद से स्टोंस को चिपका सकती हैं। स्टोन के साइज के लिए आप छोटे आकार को चुनें। ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे नाखूनों पर बड़े साइज के स्टोन अच्छे नहीं लगते हैं।

लाइन डिजाइन नेल आर्ट

लाइन डिजाइन में आजकल हैवी लुक के लिए ग्लिटर वर्क लाइन वाले नेल आर्ट बेस्ट नजर आते हैं। इस तरह के नेल आर्ट बनाने के लिए आपको मार्केट में ग्लिटर नेल पैंस आसानी से मिल जाएंगे। अलग-अलग कलर के ग्लिटर नेल पैंस की मदद से आप मनचाहा डिजाइन नाखूनों पर बना सकती हैं।

मल्टी-कलर नेल आर्ट डिजाइन

कलरफुल नेल्स पसंद करती हैं तो इस तरह के रंग-बिरंगे कलर्स के केवल डॉट-डॉट कर नाखूनों के टिप पर डिजाइन बना सकती हैं। इस तरह का डिजाइन बनाने के लिए आप टूथपिक की मदद ले सकती हैं। टूथपिक को सबसे नेल पोलिश में डूबोकर इस तरह से कलर को नाखून पर लगा सकती हैं।



फ्लोरल नेल आर्ट डिजाइन

फ्लोरल डिजाइन में आपको कई तरह के नेल आर्ट के डिजाइंस को देखने को मिल जाएंगे। आप चाहे तो सभी नाखूनों पर इस तरह से अलग कलर का इस्तेमाल करके नेल आर्ट कर सकती हैं या चाहे तो इस तरह के अलग से स्टीकर खरीदकर चिपका सकती हैं। इसमें सबसे ज्यादा पेस्टल कलर कॉम्बिनेशन को पसंद किया जाता है।



करवा चौथ पर चाँद की तरह चमकेगी आप

अगर आप करवा चौथ पर भीड़ से अलग नजर आना चाहती हैं तो आप इन पेस्टल कलर की साड़ी का चुनाव कर सकती है और इस तरह की साड़ी न्यू लुक पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। साड़ी जहां ट्रेडिशनल लुक पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है तो वहीं इसमें आप स्टाइलिश भी नजर आती हैं। साड़ी कई सारे खास मौकों पर पहन सकते हैं और अब करवा चौथ का त्योहार आ रहा है। इस खास मौके पर ज्यादातर महिलाएं साड़ी वियर करना पसंद करती हैं और अगर आप साड़ी पहनने का सोच रही हैं तो, आप पेस्टल कलर की साड़ी का चुनाव कर सकती हैं। अगर आप इन साड़ी को करवा चौथ के मौके पर स्टाइल करती हैं तो आपका लुक सबसे अलग नजर आएगा।

प्रिंटेड साटन साड़ी

इस तरह की पेस्टल कलर की प्रिंटेड साटन साड़ी आप करवा चौथ पर स्टाइल कर सकती हैं। यह साड़ी साटन फैब्रिक में है और इस तरह की साड़ी में आपका सबसे अलग नजर आएगा। इस साड़ी को 2,000 रूपये की कीमत में खरीद सकती हैं। इस साड़ी के साथ मिरर वर्क वाली ज्वेलरी साथ हो फुटवियर में आप जूती स्टाइल कर सकती हैं।

सिल्वर स्टोन वर्क टिशू साड़ी

यह सिल्वर स्टोनवर्क टिशू साड़ी भी पस्टेल कलर में है और इस तरह की तरह की साड़ी में आप भीड़ से अलग नजर आएंगी। पस्टेल कलर की इस टिशू साड़ी में बेहद ही खूबसूरत स्टोनवर्क किया हुआ है। इस साड़ी में आपका लुक रॉयल नजर आएगा और इस साड़ी को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगहों से 1,500 से 3,000 रुपये की कीमत में खरीद सकती हैं। इस साड़ी को आप स्ट्रेप वाले ब्लाउज के साथ स्टाइल कर सकती हैं साथ ही ज्वेलरी में आप चोकर स्टाइल कर सकती हैं।

पेस्टल कॉटन साड़ी

इस तरह की पेस्टल कॉटन साड़ी भी आप कई सारे खास मौकों पर पहन सकती हैं। इस तरह की साड़ी में जहां आप खूबसूरत नजर आएंगी तो वहीं आप स्टाइलिश भी नजर आएंगी। इस तरह की साड़ी आप कई सारे डिजाइन ऑप्शन के साथ खरीद सकती हैं। यह साड़ी आपको 1,000 से 2,000 रुपये की कीमत में खरीद सकती हैं।

करवाचौथ के दिन पहनें ये खूबसूरत लाल-हरी झुमकियां

स्टाइलिश दिखने के लिए आए दिन हम वार्डरोब से लेकर अपने लुक में कई तरह के बदलाव करते हैं। ट्रेडिशनल लुक में जान डालने के लिए स्टाइलिंग का रोल अहम होता है। सूट और साड़ी के साथ में सबसे ज्यादा इयररिंग्स पहनना हम बहुत पसंद करते हैं।

करवाचौथ आने वाला है और इस मौके पर हम अपने लुक में जान डालने के लिए कानों में हैवी झुमकी को स्टाइल करते हैं। तो आइये देखते हैं हरे-लाल रंग की झुमकियों के नए डिजाइंस। साथ ही, बताएंगे इन झुमकी लुक में जान डालने के आसान टिप्स-

बाली स्टाइल झुमकी डिजाइन

अपने लुक में सलवार-सूट पहन रही हैं तो खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए पंजाबी स्टाइल बाली इयररिंग्स को कानों में पहन सकती हैं। इसमें आपको झुमकी में अलग-अलग साइज और डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा इसमें मीनाकारी वर्क और स्टोन में बारीक वाले डिजाइंस को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है।



इयरकफ स्टाइल झुमकी डिजाइन

कानों को इयररिंग्स से कवर करना चाहती है तो इस तरह के हैवी डिजाइन वाले लाल और हरे कलर के कॉम्बिनेशन की झुमकियों को कानों में पहन सकती हैं। इसमें आपको गोल्डन और सिल्वर में सबसे ज्यादा डिजाइंस देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों कलर कॉम्बिनेशन को आप आसानी से किसी भी तरह के फैंसी लुक के लिए ट्राई कर सकती हैं।

कलिंग समाचार



संपादकीय

प्रधानमंत्री का डर और संसद की गरिमा

संसद सत्र को सत्ता पक्ष की तरफ से ही बाधित करना, एक साथ विपक्ष के सौ से ज्यादा सांसदों का निलंबन, सदन के भीतर एक अल्पसं यक सांसद के लिए अपशब्दों का प्रयोग, पूर्व प्रधानमंत्रियों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, महिला सांसदों के लिए अभद्र टिप्पणियां, संसद के भीतर रंगीन धुआं उड़ाना, संसद में हिंदू पंडितों से पूजा-पाठ करवाकर धर्मनिरपेक्षता की बलि चढ़ाना और सुबह सत्र संचालित करा रहे राज्यसभा सभापति का अचानक शाम को स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा और उन्हें औपचारिक विदाई तक न देना, मोदी सरकार में संसदीय परंपराओं और मर्यादा को किस तरह बार-बार तोड़ा गया, ये उसके चंद उदाहरण हैं। लेकिन अब तो संसदीय इतिहास को मुंह चिढ़ाते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जिसका अगला पायदान तानाशाही ही लगता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से चर्चा के बिना ही पारित करा दिया गया। पाठक जानते हैं कि 2 और 3 फरवरी को राहुल गांधी को सत्तापक्ष ने पूरा भाषण नहीं देने दिया। पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोद मुकुंद नरवणे की किताब के कुछ अंश कारवां पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, जिसे राहुल गांधी ने सत्यापित करने के बाद उद्धृत करना चाहा लेकिन सत्ता पक्ष की टोकाटाकी के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने उन्हें नियम 349 का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा भी कि मैं बिना उद्धृत किए ही अपनी बात रखता हूं, लेकिन जैसे ही वे चीन पर बोलने लगे, सत्ता पक्ष की घबराहट देखकर आसंदी ने उन्हें बोलने नहीं दिया। इसके बाद विपक्ष के किसी सांसद ने भाषण नहीं दिया। राहुल गांधी तो सदन में बहादुरी के साथ डटे रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कायरता की नयी मिसाल देश के सामने पेश की। वे संसद आए और फिर वापस लौट गए। बुधवार शाम पांच बजे उनका भाषण लोकसभा में निर्धारित था, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का कहना है कि उन्होंने ही प्रधानमंत्री को सदन में आने से मना किया था। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के सांसद उन पर शारीरिक हमला कर सकते थे। इस बीच हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओम बिड़ला ने कहा कि अगर कोई घटना हो जाती तो लोकतंत्र की मर्यादा तार-तार हो जाती। उसे टालने के लिए मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वह सदन में ही ना आएं। अंत में उनके ही भाषण के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर करने का फैसला हुआ। हालांकि संसद टीवी में दिख रहा है कि कांग्रेस की महिला सांसद राहुल गांधी को बोलने से रोकने का विरोध कर रही थीं और उनके हाथों में पोस्टर थे। उनका इरादा प्रधानमंत्री मोदी पर हमले का नहीं था। लेकिन अब उसी घटना की वजह से प्रधानमंत्री के बुधवार को लोकसभा में न आने की सफाई दी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी हाथ में पोस्टर थामी हुई चंद महिला सांसदों से डर गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सरकार ने इस पर कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। किन-किन महिला सांसदों पर सरकार का आरोप है, और उन आरोपों के लिए सबूत क्या हैं, यह सब देश को मालूम होना चाहिए, क्योंकि सवाल नरेन्द्र मोदी नहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है। क्या इसके बाद अमित शाह और अजित डोभाल को अपने पदों से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि जो संसद में प्रधानमंत्री को सुरक्षित न रख पाएं, वो देश की सुरक्षा का क्या खाक करेंगे। वैसे यह भी शायद पहली बार ही होगा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर संसद के भीतर ही खतरा बने। नरेन्द्र मोदी को अब देश के सामने एक सूची सौंप ही देनी चाहिए कि उन्हें किन-किन बातों से डर लगता है। इनमें चीन, डोनाल्ड ट्रंप, राहुल गांधी, कुछ नाम तो जाहिर हैं, अब शायद विपक्ष की महिला सांसदों का नाम भी जुड़ जाएं, इसके आगे मोदी और भी चीजें जोड़ सकते हैं। वैसे प्रधानमंत्री के संसद में भाषण न देने की असल वजह राहुल गांधी ही लग रहे हैं।

विकासशील देशों को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक साथ काम करना होगा

डॉ. अरुण मित्रा

%मेक अमेरिका ग्रेट अगेन% (मगा) के नारे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नज़रअंदाज़ करते हुए एकतरफ़ा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि केनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डब्ल्यूईएफ में अपने भाषण में कहा, %अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था (इंटरनेशनल ऑर्डर) टूट गयी है।

वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएएफ) की 56वीं सालाना बैठक, जो 19-23 जनवरी 2026 को दावोस में %ए स्पिरिट ऑफ़ डायलॉग% थीम के तहत हुई, वह वैश्विक व्यापार संबंधों में भारी तनाव के माहौल में हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उठाए गए कदमों ने देशों के बीच सहयोग के बने-बनाए ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यह आम तौर पर महसूस किया गया कि वैश्विक लड़ाई से बचने के लिए अलग-अलग देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपसी सहयोग और शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहना ज़रूरी है। इसी संदर्भ में, बातचीत और अन्तरराष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने के लिए एक साझे मंच के तौर पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों- संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ (अब रूस), फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और चीन- को दी गई ज़्यादा शक्ति के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र ने शांति और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने, नाभिकीय हथियारों के खतरों को जोरदार ढंग से सामने लाने, बच्चों की भलाई,सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसाधन जुटाने और इंसानों की बनाई और कुदरती, दोनों तरह की मुश्किलों से निपटने में अहम भूमिका निभायी है। इसने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने में भी मदद की है।द्यह्यश क्रूड्डुस्र - मिशन-500 या कूटनीतिक आत्मसमर्पण? भारत-अमेरिका डील के अनकहे पहलू 1964 में बनी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट (अंकटाड) का मकसद विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास से फायदा पहुंचाने में मदद करना और उन्हें बराबरी की शर्तों पर विश्व अर्थव्यवस्था में समेकित करना था। अंकटाड नीति विश्लेषण देकर, आम सहमति बनाने में मदद करके और खासकर कम विकसित देशों (एलडीसी) को तकनीकी मदद देकर व्यापार और विकास के लिए एक केन्द्रीय बिंदु के तौर पर काम करता है।

इसी तरह, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरि स एंड ट्रेड (गैट), जो 1947 की एक बहुपक्षीय संधि थी, ने टैरिफ, कोटा और सब्सिडी में कमी करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाकर युद्ध के बाद आर्थिक सेहत में सुधार को तेज़ करने की कोशिश की। 1995 में, गैटकी जगह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने ले ली। हालांकि डब्ल्यूटीओ की विकसित देशों के पक्ष में होने के लिए बहुत आलोचना हुई है, लेकिन ट्रेड-रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) और ट्रेड-रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेज़र्स (ट्रि स) जैसे समझौतों के कई प्रावधानों का इस्तेमाल विकासशील देश अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। ज़रूरी बात यह है कि इन व्यवस्थाओं ने कम से कम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक नियम-आधारित प्रणाली दी।

मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मगा) के नारे के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूटीओ और संयुक्त राष्ट्र दोनों को नज़रअंदाज़ करते हुए एकतरफ़ा व्यापार नियम फिर से लिखना शुरू कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरिस पर्यावरण समझौता सहित 66अन्तरराष्ट्रीय संगठनों, कन्वेंशन और संधियों से खुद को अलग कर लिया। जैसा कि केनडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डब्ल्यूईएफ में अपने भाषण में कहा, %अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था (इंटरनेशनल ऑर्डर) टूट गयी है। उन्होंने मध्यम आय वाले देशों से एकजुट होने की अपील की। यह ट्रंप की नीति की अप्रत्यक्ष आलोचना थी और उसका विरोध था। ट्रंप ने अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग बातचीत करके अपना टैरिफ एजेंडा लागू करने की कोशिश की, जिससे बहुपक्षवाद कमज़ोर हुआ। उनके इरादे तब और साफ़ हो गए जब उन्होंने पनामा कैनाल और गल्फ ऑफ़ मेक्सिको पर नियंत्रण और यहां तक कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करने की बात की। उन्होंने पश्चिम एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में वैश्विक तेल संसाधनों में अपनी दिलचस्पी छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। वेनेज़ुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण ने दुनिया भर में राष्ट्रीय स प्रभुता के लिए सीधी चुनौती पेश की। इस प्रक्रिया में, ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक साथियों को भी कमज़ोर किया। कई यूरोपीय देशों ने पहले इराक और लीबिया में अमेरिकी सैन्य दखल का समर्थन किया था, सीरिया में बागी ताकतों का साथ दिया था, और ईरान में अमेरिका के नेतृत्व में सरकार बदलने की कोशिशों का समर्थन किया था। गाजा में नरसंहार के दौरान भी, उन्होंने हल्के-फुल्के एतराज़ के साथ इज़राइल का साथ दिया था। पहले, वे पुराने सोवियत संघ से पैदा किए गए खतरे के जवाब में अमेरिका के साथ थे। लेकिन, जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर ज़बरदस्ती या खरीदकर कब्ज़ा करने का प्लान बताया, तो इन देशों को अमेरिका के एकतरफ़ा फ़ैसले का असर महसूस होने लगा। नतीजतन, यूरोपियन यूनियन के देश, जिनमें से कुछ कभी औपनिवेशिक ताकतें थीं, अमेरिकी चुनौती का सामना करने के लिए दूसरे तरीके खोजने लगे। यह घटनाक्रम वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता को मज़बूत करने की दिशा में एक अच्छा कदम है। इसी संदर्भ में, लंबे समय से लंबित भारत-यूरोपियन यूनियन व्यापार समझौता- जिस पर 2007 से बातचीत चल रही थी- 27 जनवरी 2026 को पूरा हुआ। इस समझौते पर सावधानी से नज़र रखनी होगी क्योंकि ईयू की बड़ी मांगें- जिसमें बौद्धिक स पदा, सरकारी खरीद, खेती और नियामक मानक भी शामिल हैं- भारत के विकास, औद्योगिक विकास, और जन कल्याण के लिए नीतिगत जगह को हमेशा के लिए रोकना चाहती हैं, जो भारत की आर्थिक स प्रभुता, रणनीतिगत स्वायत्तता और नागरिकों की भलाई का एक गलत उल्लंघन है। साथ ही, टैरिफ खत्म होने से बाजार में बाढ़ आ जाएगी। इससे विनिर्मित सामान की भी बाढ़ आ जाएगी, जिससे भारत में उद्योगीकरण में विलोम गति (डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन), बड़े पैमाने पर नौकरियों का नुकसान और सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) का विनाश होगा। इसके अलावा, ईयू की प्रस्तावित बौद्धिक स पदा प्रणाली भारत के जेनेरिक दवाओं के सेक्टर को पंगु बना देगा, जिससे ज़रूरी दवाएं महंगी हो जाएंगी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ धोखा होगा। भूमंडलीय वैश्विक राजनीति में तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, और नए रूझान सामने आ रहे हैं। इस नाजुक मोड़ पर, वैश्विक दक्षिण के विकासशील और सबसे कम विकसित देशों के लिए आपसी सहयोग, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, संप्रभुता के स मान, हथियारों की होड़ को खत्म करने और आपसी फायदे पर आधारित आर्थिक विकास की अपनी प्रणाली विकसित करना ज़रूरी है। हाल के सालों में, कई विकासशील देश मदद के लिए तेज़ी से चीन की ओर मुड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (आईसीजे) में इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका की पहल एक सकारात्मक कदम है। ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइज़ेशन (एससीओ) जैसे प्लेटफॉर्म का उभरना भी उत्साहजनक है। आज की स्थिति में यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक दक्षिण के सबसे गरीब देशों के हितों को नज़रअंदाज़ न किया जाए। भारत सहित कई विकासशील देशों में, आर्थिक विकास का फायदा समाज के कुलीन वर्गों को असमान रूप से मिला है। इसलिए, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नैम) जैसे संगठनों को फिर से मज़बूत किया जाना चाहिए, और सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग मंचों को फिर से सक्रिय किया जाना चाहिए और उन्हें वास्तव में प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियां समानता और न्याय पर आधारित होनी चाहिए।

वेनेज़ुएला के चुने हुए राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण ने दुनिया भर में राष्ट्रीय स प्रभुता के लिए सीधी चुनौती पेश की। इस प्रक्रिया में, ट्रंप ने यूरोप में अमेरिका के पारंपरिक साथियों को भी कमज़ोर किया। कई यूरोपीय देशों ने पहले इराक और लीबिया में अमेरिकी सैन्य दखल का समर्थन किया था, सीरिया में बागी ताकतों का साथ दिया था, और ईरान में अमेरिका के नेतृत्व में सरकार बदलने की कोशिशों का समर्थन किया था। गाजा में नरसंहार के दौरान भी, उन्होंने हल्के-फुल्के एतराज़ के साथ इज़राइल का साथ दिया था।

यूजीसी:पिछड़े दलितों का नेतृत्व पूरी तरह असफल

शकील अख्तर

मंडल के 35 साल बाद फिर वैसा ही सवर्ण आंदोलन हुआ और इस बार उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। मंडल के समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा था इसलिए मंडल लागू हो गया। मगर इस बार सरकार समानता के साथ नहीं थी इसलिए असमानता का पुराना जमाना बरकरार रहा। देश के कमजोर वर्ग के पास अगर नेतृत्व होता तो यूजीसी के समानता नियम इस तरह ठंडे बस्ते में नहीं जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार पर अगर दबाव पड़ता तो उसे कानून बनाकर समानता के इन नियमों को बनाए रखना पड़ता। नियम दलित पिछड़े आदिवासी छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिगत भेदभाव से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही बनाए गए थे। किसी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की वजह से नहीं।

मंडल क्यों आया था इसके बहुत सारे कारण हैं। मगर पिछड़ों के किसी आंदोलन की वजह से नहीं। वह पिछड़ों को आसमान से टपका लाभ था। उसके बाद पिछड़ों के नेताओं को सत्ता लाभ भी मिला। बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार को और उत्तर प्रदेश में मुलायम, अखिलेश यादव को। दलित उभार भी हुआ और इसकी वजह से मायावती मु यमंत्री बनीं और रामविलास पासवान बड़े नेता। शरद यादव भी बड़े नेता बने। मगर दलित पिछड़ों को क्या मिला? मंडल के 35 साल बाद फिर वैसा ही सवर्ण आंदोलन हुआ और इस बार उन्होंने जीत भी हासिल कर ली। मंडल के समय प्रधानमंत्री वीपी सिंह का राजनीतिक अस्तित्व दांव पर लगा था इसलिए मंडल लागू हो गया। मगर इस बार सरकार समानता के साथ नहीं थी इसलिए असमानता का पुराना जमाना बरकरार रहा। जिसकी वजह से रोहित वेमूला, पायल तड़वी और कई वो जो चर्चा में नहीं आ पाए जिन्दा नहीं बचे।

भारत-अमेरिका डील के अनकहे पहलू समानता नियम में क्या था? कि प्रशासन को सुनवाई करना पड़ेगी। रोहित वेमूला और पायल तड़वी का परिवार यही कहने तो सुप्रीम कोर्ट में गया था उनके बच्चों पर अन्याय होता रहा मगर शिक्षण संस्थाओं ने उनकी नहीं सुनी। अब और ज्यादा नहीं सुनेंगे! सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगाकर उन तत्वों को और ज्यादा हि मत दे दी है जो जातिगत आधार पर भेदभाव करते हैं और यह मानते हैं कि दलित आदिवासी पिछड़ों को उतनी शिक्षा का अधिकार नहीं है जितनी हमने प्राप्त की है और हमारे बच्चे कर रहे हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर स्टडी करके पिछले दो ह ते के कमेंट निकाले तो मालूम पड़ जाएगा कि वंचित समुदाय के लिए क्या क्या कहा गया है।

कौन करेगा यह काम? यहीं नेतृत्व की जरूरत मालूम पड़ती है। सवर्णों की तरफ से बताया जाने लगा कि एससी एसटी एक्ट का कितना दुरुपयोग हुआ है। सच झूठ किसी को नहीं मालूम मगर ह्वाट्सएप ग्रुपों से लेकर मीडिया तक में पहले से बनाई गई धारणा को बढ़ावा दिया जाने लगा कि नए नियमों का भी ऐसे ही दुरुपयोग होगा और ठीक यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। दुरुपयोग की आशंका। हमने पहले भी बताया है फिर बता रहे हैं कि ऐसे ही अंग्रेज कहते थे कि भारत में आजादी के दुरुपयोग की आशंका होगी। खुद वहां के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल ने कहा था।

दलित पिछड़े आदिवासी इसका जवाब कैसे देंगे? पहली बात तो खुद जागरुक नहीं है और फिर यही सवाल कि जागरुकता, चेतना आती कैसे है? जनशिक्षण से। और यह कौन करता है नेतृत्व। नेहरु अपने कैबिनेट के मंत्रियों को सैद्धांतिक क्लासों में भेजते थे। सिद्धांत मजबूत होना चाहिए। दलितों में आ बेडकर के बाद कोई जनशिक्षण करने वाला नहीं हुआ। कांशीराम ने अपने शुरूआती दौर में यह काम किया। मगर बाद में सिर्फ मायावती को मु यमंत्री बनाने में अपनी सारी ताकत लगाए रखे और मायावती उन्होंने तो दलित चेतना आगे बढ़ाने के बदले नए नियमों को समाज में तनाव बढ़ाने वाला बता दिया। वे संघ और भाजपा जितनी ही प्रतिगामी होने की कोशिश कर रही हैं। दलितों में क्या नया नेतृत्व पैदा होगा? अन्य पिछड़ों के लिए यह सवाल और ज्यादा जरूरी है।

यूजीसी के नए नियमों में पीड़ितों में पिछड़ों को भी जोड़ा गया था। इससे पहले एससी एसटी एक्ट ही काम करता था। उसमें पिछड़े नहीं थे। मायावती जो नए नियमों को समाज में तनाव पैदा करने वाला बता रही हैं उसका बड़ा कारण पिछड़ों का इन नए नियमों में आना है। बचाव पिछड़ों पर छोड़ दिया गया। मगर पिछड़ों के पास तो इस तरह का नेतृत्व बिल्कुल ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों में स्वाभिमान जगाने का काम किया। मगर वह सब पिछड़ों के लिए नहीं हो सका। उनकी जाति के लोगों को ही इसका ज्यादा फायदा मिला। व्यापक पिछड़ा हित जैसा काम नहीं हो सका। फिर जनशिक्षण के अभाव में दूसरी पिछड़ी जातियों और यादवों के बीच दूरी बढ़ती चली गई। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हुआ। मायावती की जाति में जो चेतना आई वह दूसरी दलित जातियों में पैदा करने की कोशिश ही नहीं हुई। जाहिर है कि उनकी अपनी जाति का नेतृत्व इतना काम नहीं कर पाया। नीतीश ने पिछड़ों और दलितों की एकता को महादलित और अति पिछड़ा बनाकर और तोड़ डाला। यह लोग यह नहीं देखते हैं कि अभी नए नियमों के विरोध में सारे सवर्ण बिना अपने जातिगत भेदभाव के एक साथ आए। जीते।

यहां तो कमजोर वर्ग में पहले दलित और पिछड़ों में ही भारी मतभेद है। उत्तर प्रदेश में मायावती किसी भी कीमत पर अखिलेश के साथ लड़ने को तैयार नहीं हैं। भाजपा के साथ चली जाती हैं। अभी उसी की राजनीति की मदद कर रही हैं। सरकारी नौकरी निकाल नहीं रहे हैं। तो आरक्षण खत्म हो रहा है। जो नौकरियां हैं वहां नॉट फाउन्ड सुटेबल (एनएफएस) के नाम पर आरक्षित सीटें भरी नहीं जाती हैं। दलित आदिवासी पिछड़ों के नेताओं को मालूम है कि संसद में पिछले सात साल से कोई नई भर्ती नहीं की गई है? अभी संसद चल रही है। बजट सत्र है। रोज जा रहे हैं। जरा मालूम कर के देखें कि कोई भर्ती हुई है? सब ठेके के लोगों से काम चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम जनता का पैसा बचा रहे हैं। यहां लोग बेमतलब में आकर बहस करें इसलिए बता देते हैं कि पिछले महीने ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से यह कहा। अपनी सोच के अनुरूप गढ़े हुए तर्क। सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी ऐसा ही है दुरुपयोग की आशंका।

यहां नौकरी न देना जनता का पैसा बचाना। मगर समस्या वही है। कमजोर वर्ग दलित पिछड़े आदिवासी जनता में जागरुकता का अभाव। और उनका राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक नेतृत्व कहीं दिखता नहीं। केवल सांसद विधायक मु यमंत्री मंत्री बनना नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व का मतलब नेहरू जैसा। जो लगातार प्रगतिशीलता, वैज्ञानिक चेतना फैलाते रहते थे। और सब को साथ लेकर चलते थे। यहां लिखे के अनुसार सब का नेतृत्व करते थे। गरीब कमजोर का खासतौर से। मंडल ने पिछड़ों को कुछ लाभ तो दिया। मगर जाति धर्म से ऊपर उठकर की जाने वाली राजनीति को मंडल और उसी के साथ बाबरी मस्जिद शहादत ने भारी धक्का पहुंचाया। पिछड़ों दलितों के नेता अलग हो गए। मुस्लिम में भी क्षेत्रीय दलों के साथ जाने से लेकर अपनी कयादत (नेतृत्व) के नाम पर ओवैसी के साथ जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर जो पूरे समाज को साथ लेकर चले वह नेतृत्व कमजोर हो गया। भारत में इतनी विविधता है कि कुछ मुद्दों पर अपना नेतृत्व जरूरी हो सकता है। मगर रोजमर्रा की जिन्दगी, समस्याओं के लिए जाति धर्म से ऊपर उठा नेतृत्व ही हर वर्ग के लिए और देश समाज के लिए कारामद है।



विविध समाचार



जनता को लगेगा महंगाई का झटका!, हिमाचल में 2 रुपये बढ़े ईंट के दाम, सीमेंट भी हो सकता है महंगा

शिमला (उत्तम हिन्दू न्यूज) रू पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर अब हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। प्रति ईंट 2 रुपये प्रति दाम बढ़ गए हैं, जिससे मकान, होटल और अन्य भवनों के निर्माण की लागत में इजाफा होगा। राज्य में पहले ही ईंटों का स्थानीय उत्पादन सीमित है, ऐसे में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आने वाली सप्लाई पर निर्भरता अधिक है। ईंट भट्ठों में इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमतों में भारी उछाल आया है। यह कोयला मुख्य रूप से अमेरिका, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाता है। पहले इसकी कीमत 10 से 13 हजार रुपये प्रति टन के बीच थी, जो अब बढ़कर लगभग 30 हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गई है। इस वृद्धि का सीधा असर ईंटों के दाम पर पड़ा है। युद्ध के चलते कंपनियों ने कोयले के रेट बढ़ा दिए हैं। दाम अब 30 हजार रुपये टन पहुंच गया है। जीएसटी अलग से है। ईंट भट्ठों में अमेरिका से आयात कोयला ही लगता है। पहले आस्ट्रेलिया से आता था जो बंद हो गया है। –हेमंत कपिला, चिमा ब्रिक्स ईंट उद्योग रोपड़ (पंजाब) वहीं हिमाचल प्रदेश में सीमेंट भी महंगा हो सकता है। नए वित्तीय वर्ष 2026–27 की शुरुआत के साथ ही देशभर में सीमेंट की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते से सीमेंट के प्रति बैग रेट 40 रुपये तक बढ़ सकते हैं। वर्तमान में सामान्य सीमेंट के दाम 440 प्रति बैग के बीच हैं। कंपनियों की ओर से संभावित मूल्य वृद्धि के बाद सीमेंट की नई दरें 480 रुपये प्रति बैग तक पहुंचने की आशंका है।

अमित शाह से मिले राणा सोढ़ी, सरहदी किसानों को मिलेगा जमीन का मालिकाना हक, वंदे भारत को लेकर भी बड़ी तैयारी

चंडीगढ। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में 'जीरो लाइन' और डिफेंस वायर (तार) के पार खेती करने वाले हजारों किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ सकती है। इन किसानों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिलाने की पुरानी मांग को लेकर पंजाब के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के नेतृत्व में एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अहम मुलाकात की है। इस दौरान गृह मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें किसानों के हकों के साथ–साथ सीमावर्ती जिलों के विकास से जुड़े कई बड़े और अहम मुद्दे उठाए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों शीर्ष नेताओं ने पंजाब से गए इस प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को बेहद ध्यान और धैर्य से सुना। उन्होंने रणनीतिक लिहाज से बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पंजाब के इन सीमावर्ती जिलों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए उनके उचित समाधान का पूरा भरोसा दिया है। इसके साथ ही नितिन नवीन ने जल्द ही पंजाब का दौरा करने का भी वादा किया है। इस प्रतिनिधिमंडल में अरोड़ा खत्री समाज से अनीश सिडाना, राय सिख समुदाय से हंसा सिंह कामरेड, भाजपा नेता पूरन चंद, बाबा बलविंदर सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य देवेंद्र जंग और ओबीसी नेता पुरुषोत्तम कुमार जैसे कई प्रमुख चेहरे शामिल थे। राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने बैठक में स्पष्ट किया कि पंजाब सिर्फ एक सीमावर्ती राज्य नहीं है, बल्कि यह देश की राष्ट्रीय और खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर सबसे आगे खड़ा है, इसलिए यहां के लोगों को समयबद्ध नीतियों का लाभ मिलना ही चाहिए। गृह मंत्री के सामने सबसे बड़ा और प्रमुख मुद्दा उन हजारों किसानों का उठाया गया, जो दशकों से डिफेंस वायर और जीरो लाइन के पार अपनी जमीन जोत रहे हैं। सोढ़ी ने कड़े शब्दों में मांग की कि इन किसानों को तुरंत उनकी जमीनों का मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मालिकाना हक न होने के कारण ये किसान हमेशा एक अनिश्चितता और डर के साये में जीने को मजबूर रहते हैं। सोढ़ी ने कहा कि इन किसानों को जमीन का मालिकाना हक देना सरकार का केवल कोई नीतिगत फैसला नहीं होगा, बल्कि यह उनके सम्मान और न्याय से जुड़ा एक बेहद जरूरी कदम है। किसानों के मालिकाना हक के अलावा इस ज्ञापन में फिरोजपुर–फाजिल्का रोड को फोर–लेन करने और इसे नेशनल हाईवे घोषित करने की भी पुरजोर मांग की गई है। सोढ़ी ने कहा कि रक्षा वाहनों की भारी आवाजाही के कारण आम जनजीवन काफी प्रभावित होता है, इसलिए लॉजिस्टिक तैयारियों को मजबूत करने के लिए इस सड़क का अपग्रेडेशन बेहद जरूरी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हुसैनीवाला चेक पोस्ट को व्यापार और यात्रा के लिए फिर से खोलने की जोरदार वकालत की गई है, ताकि इस इलाके की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके अलावा सीमावर्ती जिलों को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए तटबंधों (बंधों) को मजबूत करने और खुंदर गट्टी को सीधे फिरोजपुर शहर से जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की भी मांग रखी गई है, ताकि बुजुर्गों और आम लोगों को लंबा सफर न तय करना पड़े। इलाके में फैले नशे और बेरोजगारी के मुद्दे पर सोढ़ी ने कहा कि यहां औद्योगिक विकास बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोढ़ी ने फाजिल्का से श्री मुक्तसर साहिब और बठिंडा होते हुए नई दिल्ली तक एक नई 'वंदे भारत एक्सप्रेस' ट्रेन चलाने का भी शानदार प्रस्ताव गृह मंत्री के सामने पेश किया है।

पंजाब की सियासत में बड़ा उलटफेर, 1984 दंगा पीड़ितों की आवाज उठाने वाले दिग्गज वकील एचएस फूलका बीजेपी में शामिल

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता एचएस फूलका ने अपने राजनीतिक सफर में एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आधिकारिक तौर पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में उनका जोरदार स्वागत किया। इस अहम रणनीतिक मौके पर पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ भी विशेष रूप से मौजूद रहे। फूलका के इस कदम को पंजाब और राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एचएस फूलका की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को बेहद खुशी है। पुरी ने कहा कि फूलका का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। 1984 के दर्दनाक वाकये का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि वह कोई साधारण दंगा नहीं था, बल्कि सिख समुदाय के बेगुनाह लोगों का बेरहमी से खून बहाया गया था। फूलका ने उन अत्याचारों के खिलाफ शुरुआत से ही कानूनी और सामाजिक जंग लड़ी है, जिसकी बदौलत ही साल 2023 में इस नरसंहार के एक बड़े आरोपी को सजा दिलवाना संभव हो सका। फूलका के भाजपा में शामिल होने को लेकर हरदीप पुरी ने एक दिलचस्प पुरानी बात भी साझा करते हुए सबको चौंका दिया। उन्होंने बताया कि एचएस फूलका का भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता कोई नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। साल 1992 में जब दिल्ली में भाजपा ने अपनी सरकार बनाई थी, तब फूलका ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना के एडवाइजर (सलाहकार) के रूप में अपनी अहम सेवाएं दी थीं। अब एक बार फिर उनके भाजपा से जुड़ने पर पार्टी को उनके लंबे अनुभव और सिख समुदाय के बीच उनकी गहरी और साफ–सुथरी छवि का बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

4 साल बाद क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा बड़ा सच आने वाला है सामने?

चंडीगढ। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत को 29 मई 2026 को 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन हत्या का दावा करने वाला मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अब भी फरार है। हालांकि अब लगता है कि सिंगर की हत्या से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। ऐसा हम नहीं, बल्कि उनके आधिकारिक अकाउंट से जारी हुआ पोस्ट का दावा है, जिसे देखकर फैंस भी आशंका लगा रहे हैं कि कुछ दबे राज खुलने वाले हैं, जिन्हें हत्या के वक्त अनदेखा कर दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें 25 मार्च 2021 की कुछ घटनाओं का समयानुसार जिक्र किया गया है। पोस्टर में सिंगर के हलेवी से निकलने से लेकर घर वापस आने का समय लिखा है और साथ ही उनकी हवेली में लगे कैमरों की संख्या भी लिखी है। पोस्टर में 3–4 गनमैन का भी जिक्र किया गया है और अक्सर पिता और 3–4 दोस्तों के साथ ज्यादातर समय बिताने की जानकारी दी गई है। पोस्टर को 'आईज ऑन मी' के नाम से जारी किया गया है। हालांकि यह कोई नया गाना है या कुछ और, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। पोस्टर को देखकर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि हत्या से पहले की कुछ गतिविधियों को दिखाने की कोशिश की गई है।

वैचारिक मंथन के लिए कछुए के समान धैर्य व स्थिरता की आवश्यकता

भगवान विष्णु के दशावतारों में द्वितीय कच्छप अवतार अर्थात कूर्मावतार न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि धैर्य, स्थिरता और सामूहिक प्रयास के महत्व का एक गहरा प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को पारिजात पुष्पों की माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया, जिसने उसे कुचल दिया। इससे क्रोधित होकर दुर्वासा ने देवताओं को श्रीहीन अर्थात शक्ति और वैभव विहीन होने का श्राप दे दिया। शक्तिहीन देवताओं पर असुरों ने विजय प्राप्त कर ली।अपनी खोई हुई शक्ति और अमृत प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। मंथन शुरू होते ही मंदराचल पर्वत का कोई आधार न होने के कारण वह समुद्र के तल (क्षीर सागर) में धंसने लगा। तब सृष्टि को असंतुलन से बचाने और मंथन को सफल बनाने के लिए भगवान विष्णु ने एक विशाल कच्छप अर्थात कछुए का रूप धारण किया और समुद्र के तल में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया।कछुए की पीठ पर पर्वत का भार था, लेकिन भगवान विष्णु के लिए वह एक सुखद खुजली के समान था। कूर्मावतार के सहयोग से हुए इस मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें लक्ष्मी (सम्पत्ति), धन्वंतरि (आरोग्य), ऐरावत, कामधेनु और अंत में अमृत शामिल थे। इनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट महत्व है। ये रत्न देवताओं और असुरों के बीच उनकी उपयोगिता के आधार पर बांटे गए थे।कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट कर शांत रहता है, जो यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में एकाग्रता और धैर्य ही सफलता की कुंजी है।जैसे कछुए ने पूरे ब्रह्मांडीय मंथन को आधार दिया, वैसे ही परमात्मा हमारे जीवन के हर संघर्ष के अदृश्य आधार हैं।कच्छप अवतार हमें सिखाता है कि जीवन में जब विचारों का मंथन होता है, तो मन को विचलित होने से बचाने के लिए स्थिरता अर्थात कछुए जैसी पीठ की आवश्यकता होती है। बिना एक मजबूत आधार और संकल्प के हम अपने प्रयासों का फल अर्थात अमृत प्राप्त नहीं कर सकते।यह मंथन हमें सिखाता है कि सफलता (अमृत) प्राप्त करने के लिए पहले विष जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अंत तक धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। भगवान विष्णु का कूर्मावतार केवल सतयुग की एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि आधुनिक युग के प्रबंधन, मनोविज्ञान और जीवन दर्शन के लिए एक जीवंत मार्गदर्शिका है। आज की भागदौड़ भरी और अस्थिर दुनिया में इस अवतार की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है।आज की दुनिया अनिश्चितता से भरी है। जिस तरह समुद्र मंथन के समय मंदराचल पर्वत डूबने लगा था, वैसे ही आज के दौर में बड़े प्रोजेक्ट्स या रिश्ते बिना ठोस आधार के बिखर जाते हैं। कच्छप अवतार सिखाता है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए स्थिरता और एक मजबूत आधार का होना अनिवार्य है।कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने खोल के भीतर समेटने की क्षमता रखता है। आज के डिजिटल युग में, जहां ध्यान भटकाने वाले साधन अनंत हैं, कूर्मावतार हमें सिखाता है कि सफलता के लिए फोकस और बाहरी शोर से स्वयं को काटकर अंतर्मुखी होना कितना जरूरी है। समुद्र मंथन कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं थी। कूर्मावतार ने उस भारी बोझ को तब तक अपनी पीठ पर टिकाए रखा जब तक अमृत नहीं निकल गया। यह आधुनिक कॉर्पोरेट जगत और स्टार्टअप कल्चर के लिए बड़ा सबक है कि अमृतअर्थात सफलता रातों–रात नहीं मिलती, उसके लिए अथाह धैर्य की आवश्यकता होती है। समुद्र मंथन में देवता और असुर अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां दोनों शामिल थे। कच्छप अवतार ने एक न्यूट्रल आधार बनकर दोनों को जोड़े रखा। वर्तमान समाज और राजनीति में यह संदेश है कि बड़े बदलाव के लिए परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच भी एक साझा धरातल तैयार करना सामूहिक प्रयास और नेतृत्व की असली पहचान है। मंथन में पहले विष अर्थात चुनौतियांनिकलता है, फिर रत्न। कच्छप अवतार वह नींव है, जो उस पूरे संघर्ष का भार सहती है। यह हमें मानसिक मजबूती सिखाता है कि लक्ष्य प्राप्ति के दौरान आने वाले संघर्षों से घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए।आज के तुरंत फल की इच्छा रखने वाले युग मेंकच्छप अवतार हमें याद दिलाता है कि स्थायी सफलता केवल स्थिरता, संयम और अटूट संकल्प की पीठ पर ही टिकी रह सकती है। आधुनिक प्रबंधन की दृष्टि से कच्छप अवतारएक बेहतरीन केस स्टडी है। यह अवतार हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े संगठन या प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए किन रणनीतियों की आवश्यकता होती है? किसी भी व्यवसाय अथवा स्टार्टअप की सफलता उसके आइडिया से ज्यादा उसके फाउंडेशन पर निर्भर करती है। जिस तरह मंदराचल पर्वत अर्थात प्रोजेक्ट बिना कच्छप अर्थात मजबूत आधार के डूबने लगा था, वैसे ही बिना मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और बैकअप प्लान के बड़े से बड़ा विजन फेल हो सकता है। प्रबंधन में इसे बॉटम–अप अप्रोच कहते हैं।मंथन के दौरान जब अफरातफरी मची, तब कच्छप विचलित नहीं हुए। एक अच्छे मैनेजर का गुण यही है कि वह संकट के समय टीम को बिखरने न दे और स्वयं शांत रहकर दबाव को सहन करे। कूर्मावतार इमोशनल इंटेलिजेंस और स्थिरता का सबसे बड़ा उदाहरण है।समुद्र मंथन में दो विपरीत विचारधाराएं अर्थात देवता और असुर एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रही थीं। एक कुशल लीडर वही है जो विरोधी पक्षों को एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट कर सके और उन्हें एक मंच प्रदान करे।मंथन के लिए उपलब्ध संसाधनों अर्थात वासुकी नाग, मंदराचल पर्वत का सही उपयोग तभी संभव हुआ जब भगवान ने कच्छप रूप में उन्हें सपोर्ट दिया। मैनेजमेंट में इसे सपोर्ट फंक्शन कहते हैं, जो फ्रंटलाइन ऑपरेशन्स को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।अमृत निकलने में बहुत समय लगा और बीच में विष भी निकला। कच्छप अवतार हमें सिखाता है कि परिणाम के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान दें। यदि प्रोसेस सही है और आधार मजबूत है, तो अंत में लाभ मिलना निश्चित है।भगवान विष्णु ने इस अवतार में कोई उपदेश नहीं दिया, न ही युद्ध किया। वे चुपचाप समुद्र के नीचे रहकर पूरे मिशन को सफल बनाते रहे। इसे सर्वेंट लीडरशिप कहा जाता है, जहां नेता खुद पर्दे के पीछे रहकर अपनी टीम को चमकने का मौका देता है।आज के कॉर्पोरेट समुद्र मंथन में वही कंपनियां और लीडर्स टिक पाते हैं जिनमें कच्छप जैसी सहनशीलता, दूरदर्शिता और अडिग रहने की क्षमता होती है। भगवान विष्णु का कूर्मावतार और कछुए की जैविक विशेषताएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथा में कछुए के चुनाव के पीछे प्रकृति के ठोस वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण छिपे हैं।एक कछुए की सबसे बड़ी विशेषता उसका कवच है। यह जैविक रूप से इतना मजबूत होता है कि भारी दबाव को भी सहन कर सकता है।समुद्र मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत का अथाह भार उठाने के लिए ऐसे ही एक प्राकृतिक आधार की आवश्यकता थी, जो टूटता नहीं। कछुए की पीठ का धनुषाकार आकार वजन को समान रूप से वितरित कर देता है।कछुए में अपने हाथ, पैर और सिर को अपने कठोर कवच के भीतर समेटने की अद्भुत क्षमता होती है। इसे जीव विज्ञान में त्याग अर्थात रिट्रेक्शन कहते हैं।श्रीमद्भगवद्गीता में भी कछुए का उदाहरण दिया गया है। जैसे कछुआ खतरों को देखकर सिमट जाता है, वैसे ही एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति बाहरी आकर्षणों से अपनी इंद्रियों को हटाकर लक्ष्य पर केंद्रित रहता है।कछुआ पृथ्वी पर सबसे अधिक जीवित रहने वाले प्राणियों में से एक है। इसकी कुछ प्रजातियाँ 150–200 वर्ष तक जीती हैं)। इनकी मेटाबॉलिज्म दर बहुत धीमी होती है, जिससे ये बहुत धैर्यवान और शांत दिखते हैं।समुद्र मंथन एक लंबी प्रक्रिया थी। इसके लिए ऐसे जीव की आवश्यकता थी जो उतावला न हो और लंबे समय तक बिना विचलित हुए अमृत निकलने की प्रतीक्षा कर सके।कछुए लंबे समय तक अपनी सांस रोक सकते हैं और पानी की गहराई में स्थिर रह सकते हैं।यह विशेषता प्राणायाम और कुंभक अर्थात सांस रोकने का प्रतीक है। कूर्मावतार क्षीर सागर की गहराइयों में बिना विचलित हुए स्थिर रहे, जो गहरी समाधि और मानसिक शांति को दर्शाता है।कछुआ जल और थल दोनों के अनुकूल होता है। हालांकि कछुआ मुख्य रूप से जमीन पर रहता है, पर अवतार कच्छप समुद्र के भीतर था।यह जीव की लचीलापन को दर्शाता है कि वह विषम परिस्थितियों (समुद्र के तल) में भी अपने अस्तित्व और कर्तव्य (पर्वत को थामना) को बनाए रखता है।कूर्मावतार प्रकृति के उस धीमी लेकिन स्थिर सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है, जो अंततः जीत हासिल करता है। जैविक रूप से कछुआ रक्षात्मक मजबूतीका प्रतीक है, जो किसी भी सृजन (मंथन) के लिए सबसे पहली जरूरत है। वैज्ञानिक दृष्टि से विष्णु के दशावतार को जीव विकास के सिद्धांत के समानांतर देखा जाता है।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, शनिवार 21 नवम्बर 2026 | पृष्ठ-6

अकवान का असर अभी बाकी! तेज हवाओं और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग सतर्क

भुवने श्वर २०/११ (संवाददाता): बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान अकवान की तीव्रता में शुक्रवार को कमी दर्ज की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर चक्रवाती तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन यानी गहरे अवदाब में बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार, यह प्रणाली अगले छह घंटों के दौरान और कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल सकती है। हालांकि चक्रवात की ताकत कम होने के बावजूद ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में तेज हवाओं तथा भारी बारिश का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की सलाह दी है।भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से शुक्रवार दोपहर जारी राष्ट्रीय बुलेटिन के अनुसार, चक्रवात अकवान पिछले छह घंटों के दौरान करीब 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा की ओर बढ़ा। इस दौरान इसकी तीव्रता धीरे-धीरे कम होती गई और सुबह 11 बजकर 30 मिनट पर यह दक्षिण तटीय ओडिशा के ऊपर डीप डिप्रेशन में बदल गया।मौसम विभाग ने बताया कि सुबह 11:30 बजे इस प्रणाली का केंद्र अक्षांश 19.6 डिग्री उत्तर और देशांतर 84.9 डिग्री पूर्व के आसपास स्थित था। यह गोपालपुर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर, पुरी से 100 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिणपश्चिम और आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व में केंद्रित था।

आईएमडी के अनुसार, यह मौसम प्रणाली ओडिशा के ऊपर उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। अगले छह घंटों में इसके डिप्रेशन में बदलने और उसके बाद के छह घंटों में और कमजोर होकर एक सुस्पष्ट नि न दबाव क्षेत्र में परिवर्तित होने का अनुमान है। मौसम विभाग गोपालपुर स्थित डॉपलर मौसम रडार की सहायता से इस प्रणाली की लगातार निगरानी कर रहा है।इससे पहले शुक्रवार सुबह चक्रवाती तूफान अकवान ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के तटीय क्षेत्रों को पार किया था। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 7 बजकर 30 मिनट से 8 बजकर 30 मिनट के बीच यह तूफान गोपालपुर के नजदीक तट से टकराया। उस समय हवाओं की र तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जबकि झोंकों के साथ हवा की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी।तूफान के तट से टकराने के दौरान समुद्र में ऊंची लहरें उठीं और तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में चक्रवात के प्रभाव से जनजीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन ने पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और राहत संबंधी तैयारियां की थीं। मौसम विभाग के ताजा आकलन



के अनुसार, डीप डिप्रेशन के दौरान हवाओं की गति लगभग 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई, जबकि तेज झोंकों के साथ यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच रही थी। शुक्रवार शाम साढ़े पांच बजे तक प्रणाली के डिप्रेशन में बदलने पर हवा की गति घटकर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान जताया गया है।चक्रवात की तीव्रता कम होने के बावजूद मौसम विभाग ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी रखी है। आईएमडी के अनुसार, 20 नवंबर को ओडिशा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से तटीय और निचले इलाकों में जलभराव तथा अचानक बाढ़ जैसी परिस्थितियों का जोखिम बना हुआ है।मौसम विभाग ने ओडिशा के गंजाम, गजपति, पुरी, जगतसिंहपुर, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज और कुछ अन्य जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान अचानक बाढ़ का मध्यम जोखिम भी जताया है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा होने और स्थानीय स्तर पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

चक्रवात अकवान के कमजोर होने के बाद भी इसका प्रभाव पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 20 और 21 नवंबर को पूर्वी छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है।इससे विशेष रूप से ओडिशा की सीमा से लगे क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की आशंका है।वहीं झारखंड में 20 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 21 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गंगीय पश्चिम बंगाल में भी 20 नवंबर को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण-पूर्व बिहार में 21 नवंबर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।समुद्री परिस्थितियों को लेकर भी मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी दी है। दक्षिण ओडिशा तट के आसपास समुद्र में तेज हवाएं चलने और ऊंची लहरें उठने की संभावना बनी हुई है। शुक्रवार दोपहर तक दक्षिण ओडिशा तट पर हवाओं की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान था, जो झोंकों के साथ 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती थी।हालांकि शाम तक हवाओं की गति धीरे-धीरे कम होने की संभावना जताई गई है। समुद्र में प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए मछुआरों को प्रभावित समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी आधिकारिक मौसम चेतावनियों का पालन करने की सलाह दी गई है।चक्रवात अकवान के कारण ओडिशा में पहले से व्यापक स्तर पर राहत और बचाव की तैयारियां की गई थीं। संवेदनशील तटीय क्षेत्रों से बड़ी सं या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। शुक्रवार दोपहर तक उपलब्ध प्रशासनिक जानकारी के अनुसार, ओडिशा में चक्रवात से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की सूचना नहीं थी। हालांकि प्रभावित इलाकों में स्थिति का आकलन जारी था।मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, चक्रवाती प्रणाली के कमजोर पड़ने से तेज हवाओं का खतरा धीरे-धीरे कम हो सकता है, लेकिन इससे जुड़ी बारिश तुरंत समाप्त होना जरूरी नहीं है। इसलिए अगले कुछ घंटों के दौरान प्रभावित राज्यों में सतर्कता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा।फिलहाल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग चक्रवात की गति और तीव्रता पर लगातार नजर रख रहा है। शुक्रवार शाम तक इसके डिप्रेशन और देर रात तक सुस्पष्ट नि न दबाव क्षेत्र में बदलने का अनुमान है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार, चक्रवात कमजोर होने के बावजूद बारिश, तेज हवाओं और जलभराव से जुड़ी चुनौतियां कुछ क्षेत्रों में बनी रह सकती हैं।

ओडिशा में अकवान की धमकी के चलते पर्यटन स्थल बंद किए

भुवनेश्वर २०/११ (संवाददाता): चक्रवात अकवन के खतरे के बीच, अधिकारियों ने गंजम में चिकिती से खल्लीकोट तक तटीय क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और रायगडा और गजपति जिलों में संवेदनशील पर्यटन स्थलों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी है। गंजम कलेक्टर वी कीर्ति वासन ने कहा कि एहतियात के तौर पर 25,000 से अधिक लोगों को पहले ही संवेदनशील तटीय इलाकों से निकाला जा चुका है। अधिकारियों को आसन्न चक्रवात के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित अधिकारियों को मोबाइल नेटवर्क व्यवधान की स्थिति में संचार की सुविधा के लिए अधिकारियों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। वासन ने कहा कि प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ओडीआरएएफ, वन विभाग और अग्निशमन सेवा कर्मियों को अलर्ट पर रखा है। प्रशासन ने अत्यधिक भारी बारिश के लिए आईएमडी की लाल चेतावनी के मद्देनजर आंगनवाड़ी



केंद्रों के अलावा सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों को 20 नवंबर तक बंद करने का आदेश दिया है। यदि आवश्यक हुआ तो शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग अस्थायी चक्रवात आश्रयों के रूप में किया जाएगा। अधिकारियों को पीने के पानी, बिजली, पावर बैकअप और स्वच्छता सहित आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ताकि इमारतों में कमजोर क्षेत्रों से निकाले गए लोगों को समायोजित किया जा सके। तेज हवाओं और भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग सतर्क रायगड़ा में, प्रशासन ने झरने, नदी तट, बांध, जलाशय और ट्रैकिंग मार्गों सहित संवेदनशील स्थानों पर सभी पर्यटन और मनोरंजक गतिविधियों को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। जिला पर्यटन अधिकारी को भारी बारिश और तेज हवाओं के पूर्वानुमान के मद्देनजर तत्काल एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के समन्वय से बैरिकेड्स और चेतावनी साइनबोर्ड के माध्यम से संवेदनशील स्थानों तक सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित की जाएगी।

ओडिशा के क्योंझर में आदिवासियों का बड़ा प्रदर्शन

क्योंझर २०/११ (संवाददाता): बसंतपुरा घटना में न्याय के अलावा अपने संवैधानिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और पारंपरिक पूजा स्थलों की सुरक्षा की मांग को लेकर 20,000 से अधिक आदिवासियों ने बुधवार को क्योंझर में कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी, जो पड़ोसी राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल से भी आए थे, पारंपरिक पोशाक पहने हुए थे और अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए कलेक्टर कार्यालय के बाहर एकत्र हुए थे और उनके पास पारंपरिक हथियार थे।माझी परगना महल और मिलिता आदिवासी कल्याण मंच के बैनर तले आयोजित विशाल सभा ने क्योंझर शहर में सामान्य जीवन को बाधित कर दिया, कई सड़कों पर बड़ी भीड़ के कारण यातायात की आवाजाही प्रभावित हुई। बीजू जनता दल (बीजद) ने विरोध को अपना समर्थन दिया था। यह प्रदर्शन घासीपुरा थाना क्षेत्र के बसंतपुरा गांव में संथाल समुदाय के पारंपरिक पूजा स्थल जाहेर थान, जिसे जाहेरा के नाम से भी जाना जाता है, को अपवित्र करने के कुछ दिनों बाद हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनकी पारंपरिक पूजा प्रथाओं में बाधा डालने का प्रयास किया गया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं।

चक्रवात के चलते ओडिशा विधानसभा स्थगित

भुवनेश्वर २०/११ (संवाददाता): ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने शुक्रवार को चक्रवात अकवन के कारण सदन की कार्यवाही 23 नवंबर की सुबह तक के लिए स्थगित कर दी, जो दिन के दौरान गोपालपुर के पास पहुंचा था। यह निर्णय एक सर्वदलीय बैठक में लिया गया, जिसके बाद पाधी ने स्थगन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि विधायकों को चक्रवात अकवन के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में लोगों की सहायता करनी चाहिए। अध्यक्ष ने कहा, सदन दो दिनों के लिए स्थगित रहेगा और कार्यवाही 23 नवंबर को सुबह 10.30 बजे से फिर से शुरू होगी।उन्होंने कहा, विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य इस



बात पर सहमत हुए कि सदन को शुक्रवार और शनिवार के शेष घंटों के लिए स्थगित करने की जरूरत है। रविवार को छुट्टी है। इसलिए विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के लिए दो दिन मिलेंगे। शुक्रवार सुबह 10.30 बजे जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, बीजद और कांग्रेस के सदस्य तख्तियां लेकर सदन के वेल में आ गए और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। बीजद विधायकों ने सदन का सारा कामकाज स्थगित कर चक्रवात और बाढ़ राहत कार्यों पर चर्चा कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने में विफल रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के साथ कोटिया सीमा विवाद को लेकर नारेबाजी की और विधानसभा में इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। सदन चलाने में असमर्थ अध्यक्ष ने पहले तो कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी. जैसे ही सदस्य दोबारा एकत्र हुए, पाढ़ी ने सोमवार सुबह तक के लिए स्थगन की घोषणा की।

ओडिशा हाईकोर्ट ने हॉकी इंडिया की रोक हटाने की याचिका खारिज की

कटक २०/११ (संवाददाता): उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हॉकी इंडिया द्वारा दायर अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी कार्यकारी समिति और पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित 5 दिसंबर के चुनावों पर 6 नवंबर के स्थगन आदेश को हटाने की मांग की गई थी। अब अगले आदेश तक चुनाव नहीं हो सकेंगे।न्यायमूर्ति आरके पटनायक ने हॉकी इंडिया और हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा (एचएओ) की ओर से दलीलें सुनने के बाद आवेदन खारिज कर दिया। यह रोक मु य याचिका की नौ दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक लागू रहेगी। हॉकी इंडिया ने यह तर्क देते हुए रोक वापस लेने की मांग की थी कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। याचिका का विरोध करते हुए एचएओ ने दलील दी कि चुनाव कैलेंडर प्रकाशित करने वाली समिति पहले ही अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है और इसलिए उसमें वैधता का अभाव है। एचएओ का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पीके रथ ने कहा, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति पटनायक ने हॉकी इंडिया के अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया।

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

विज्ञापन सं. R&P/324/2026 **दिनांक: 28.10.2026**

दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन सीआईई प्रायोगिक बेसिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) एवं सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 18.11.2026 अथवा रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की अंतिम तिथि से दो सप्ताह के भीतर इनमें से जो भी बाद में हो, निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं तथा "Work with DU" शीर्षक के अंतर्गत "Advertisement - Departments" पर क्लिक करें।

किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

CBC 21231/11/0023/2627 **कुलसचिव**

जंगल में हाथी के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, शरीर पर चोट के निशान

देवगढ़ २०/११ (संवाददाता):ओडिशा के देवगढ़ जिले में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को एक हाथी के बच्चे का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई। जिले की रियामल वन रेंज के अंतर्गत गदागदा गांव के पास बिजखुजा रिजर्व फॉरेस्ट में हाथी का बच्चा मृत अवस्था में पाया गया। यह स्थान रामभादेवी रिजर्व फॉरेस्ट के नजदीक स्थित है। वन विभाग को सुबह करीब 7 बजकर 40 मिनट पर घटना की सूचना मिली, जिसके बाद वरिष्ठ वन अधिकारी और विशेष टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं। प्रारंभिक जांच में हाथी के बच्चे की मौत प्राकृतिक कारणों से होने की आशंका जताई गई है। अधिकारियों को संदेह है कि हाथियों के आपसी संघर्ष के दौरान लगी चोटों के कारण उसकी मौत हुई हो सकती है। हालांकि, शव पर बाहरी चोटों के निशान मिलने से मौत की वास्तविक वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

वन विभाग को मिली सूचना वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, शुक्रवार सुबह लगभग 7:40 बजे रेंगलबेदा सेक्शन के फॉरेस्टर ने हाथी के बच्चे की मौत की जानकारी दी। सूचना में बताया गया कि रियामल रेंज के अंतर्गत गदागदा गांव के समीप स्थित बिजखुजा रिजर्व फॉरेस्ट में हाथी का एक बच्चा मृत पाया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया और अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। हाथी जैसे संरक्षित वन्यजीव की मौत की घटना होने के कारण जांच को प्राथमिकता दी गई।

वन विभाग के लिए इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण सवाल



यह है कि हाथी के बच्चे की मौत किन परिस्थितियों में हुई। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर मौत के पीछे प्राकृतिक कारणों की आशंका जताई गई है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष के लिए विस्तृत जांच आवश्यक है। डीएफओ और एसीएफ समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे घटना की जानकारी मिलते ही देवगढ़ के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर (डीएफओ) वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उनके साथ असिस्टेंट कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट (प्रशासन), रियामल रेंज ऑफिसर और अन्य वन कर्मचारी भी मौजूद रहे।

इसके अलावा रैपिड रिस्पॉन्स टीम (आरआरटी) और रेंज स्क्वॉड को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। सभी टीमों ने मिलकर घटना की परिस्थितियों का प्रारंभिक निरीक्षण किया। वन अधिकारियों ने उस स्थान की जांच शुरू की, जहां हाथी के बच्चे का शव मिला था। शव की स्थिति और उसके शरीर पर मौजूद चोटों के निशान जांच के महत्वपूर्ण पहलू हैं। अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या हाथी के बच्चे की मौत जंगल में हाथियों के बीच हुए किसी संघर्ष का परिणाम थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण रहा।

शव पर मिले बाहरी चोटों के निशान प्रारंभिक जांच के दौरान हाथी के बच्चे के शव पर बाहरी चोटों के निशान पाए गए हैं। इन निशानों के आधार पर वन अधिकारियों ने आशंका जताई है कि हाथियों के आपसी संघर्ष के दौरान बच्चा घायल हुआ होगा। हालांकि, केवल बाहरी चोटों के आधार पर मौत का निश्चित कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए शव का विस्तृत परीक्षण और अन्य परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। वन विभाग की शुरुआती जांच में मौत को प्राकृतिक कारणों से जुड़ा संभावित मामला माना जा रहा है। अधिकारियों ने हाथियों के बीच संघर्ष की संभावना भी व्यक्त की है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि घटना के समय संबंधित वन क्षेत्र में कितने हाथी मौजूद थे या किसी हाथी समूह के बीच संघर्ष हुआ था। इन तथ्यों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। प्राकृतिक कारणों से मौत होने की आशंका वन विभाग के अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के आधार पर आशंका जताई है कि हाथी के बच्चे की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई हो सकती है। विशेष रूप से हाथियों के बीच आपसी संघर्ष की संभावना पर ध्यान दिया जा रहा है। जंगल में हाथियों के बीच कभी-कभी आपसी संघर्ष की घटनाएं सामने आती हैं। ऐसी परिस्थितियों में छोटे हाथियों को गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है।

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

विज्ञापन सं. R&P/325/2026 **दिनांक: 29.10.2026**

दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक (अतिरिक्त पद) के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19.11.2026 अथवा रोजगार समाचार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर इनें से जो भी बाद में हो, निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं तथा "Work with DU" शीर्षक के अंतर्गत "Advertisement - Departments" पर क्लिक करें।

किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

CBC 21231/11/0019/2627 **कुलसचिव**

दिल्ली विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF DELHI

विज्ञापन सं. R&P/326/2026 **दिनांक: 30.10.2026**

दिल्ली विश्वविद्यालय में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक एवं विधिक सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.112026 अथवा रोजगार में विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से दो सप्ताह के भीतर इनमें से जो भी बाद में हो, निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं तथा "Work with DU" शीर्षक के अंतर्गत "Advertisement - Departments" पर क्लिक करें।

किसी भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र को केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा।

CBC 21231/11/0021/2627 **कुलसचिव**